लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है: राष्ट्रपति कोविंद

जनहितैषी

हिन्दी दैनिक

R.N.I. No. 63177/95 वर्ष:27 अंक: 100 दिनांक: 25-03-2022 शुक्रवार मूल्य : 100 पैसा पृष्ठ:4 अहमदाबाद M

चीन के विदेश मंत्री वांग यी दिल्ली पहुंच गए हैं। वह कल एनएसए अजित डोभाल और विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे।

अब वन नेशन वन इलेक्शन' की बारी राज्यसभा में गूंजा मुद्दा

नई दिल्ली (ईएमएस)। राज्यसभा में विभिन्न दलों के सदस्यों ने विभिन्न मुद्दे उठाये जिनमें ''एक राष्ट्र, एक चुनाव'', ओडिशा में विधानपरिषद के गठन, प्रधानमंत्री मातृत्व योजना के तहत आवेदन की प्रक्रिया को आसान बनाने और बेघर बच्चों (स्ट्रीट चिल्ड्रेन) के पुनर्वास के मुद्दे शामिल थे। शून्य काल में भारतीय जनता पार्टी के डॉ. डी पी वत्स ने ''एक राष्ट्र, एक चुनाव'' का मुद्दा उठाया और कहा कि 1967 के बाद संविधान के अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल करते हुए संयुक्त विधायक दल की सरकारों को कार्यकाल के बीच में ही बर्खास्त किया गया तथा इसके बाद देश में 'एक राष्ट्र, लगातार' चुनाव की स्थिति हो गई। अलग अलग समय पर होने वाले चुनावों को देश के संसाधनों पर बड़ा भार बताते हुए वत्स ने कहा, ''राष्ट्र हित को मद्देनजर रखते हुए मैं सभी राजनीतिक दलों, वह चाहें सरकार में हों या विपक्ष में, से आग्रह करूंगा कि दस विषय पर एक आम सहमति बनाई जाए। इसके लिए कोई रास्ता निकाला जाए ताकि देश के संसाधनों पर भार कम हो और पांच साल में एक बार विधानसभा, लोकसभा और शहरी निकायों के चुनाव हों। ऐसा होता है तो देश हित में बहुत अच्छा होगा।'' ओडिशा से बीजू जनता दल के सदस्य मुजीबुल्लाह खान ने राज्य में विधान परिषद के गठन के लिए केंद्र सरकार से आवश्यक कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि ओडिशा की विधान सभा ने इस आशय का संकल्प 2018 में सर्वसम्मति से पारित कर केंद्र सरकार को भेजा। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों राज्यसभा में एक लिखित सवाल के माध्यम से इस प्रस्ताव की स्थिति की जानकारी मांगी गई तो सरकार की ओर से जवाब में कहा गया कि उसे इस संकल्प का कोई ऐसा दस्तावेज नहीं मिला है। उन्होंने कहा विधान सभा से संकल्प पारित होने के बाद भारत सरकार के पास कागज आया था। मंत्री महोदय कह रहे हैं कि वह कागज मिल नहीं रहा है।...मतलब कहीं गुमा दिये होंगे? यह तो बड़ी अजीब बात है। हम सब स्कूलों में पढ़ते थे तब कागज गुम हो जाया करते थे...यहां तो संसद में कागज गुम हो रहा है...सरकार में भी कागज गुम हो रहा है। खान ने कहा कि इसके बाद विधान सभा के अध्यक्ष ने फिर से संकल्प संबंधी आवश्यक दस्तावेज की प्रति केंद्र सरकार को भेजी है। उन्होंने कहा, ''हमारा अनुराध है कि विधान परिषद गठन करने का जो संकल्प विधान सभा से पारित हुआ है, उसका सम्मान करते हुए आवश्यक कदम उठाइए।

रसोई गैस के बाद सीएनजी और पीएनजी हुई महंगी

नई ?दिल्ली (ईएमएस)। पेट्रोल-डीजल सहित रसोई गैस गैस की कीमतें बढ़ने के बाद गुरुवार को सीएनजी और पीएनजी की कीमतें बढ़ाई गई हैं। घरेलू पीएनजी की कीमत में 1.00 रुपए प्रति एससीएम की वृद्धि की गई है, हालांकि बढ़ी हुई कीमतें पूरे देश में नहीं बल्कि दिल्ली और उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में लागू होंगी। इसके अलावा राजधानी दिल्ली में सीएनजी के दामों में 50 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। राहत की बात यह है कि पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किए गए हैं। इससे पहले लगतार दो दिन इसमें 80-80 पैसे की वृद्धि की गई थी। वहीं मंगलवार को एलपीसी रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में भी 50 रुपए की बढ़ोतरी की गई थी। पाइप्ड नैचुरल गैस यानि पीएनजी गुरुवार से और महंगी हो गई है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (आईजीएल) ने दिल्ली-एनसीआर में पीएनजी की कीमतों में एक रुपए प्रति एससीएम की वृद्धि की है। कीमतों में यह बढ़ोतरी 24 मार्च गुरुवार से लागू हो रही है। ऐसे में अब दिल्ली में पीएनजी गैस 36.61 रुपए से बढ़कर 37.61 रुपए प्रति एससीएम हो गई है। गौतम बुद्ध नगर में भी पीएनजी गैस के लिए 35.86 रुपए प्रति एससीएम अब चुकाने होंगे। इसके अलावा सीएनजी के दाम में 50 पैसे प्रति किलो की वृद्धि की गई है। यह वृद्धि भी गुरुवार सुबह 6 बजे से लागू हो गई है। दिल्ली में सीएनजी की कीमत अब 59.01 रुपए प्रति किलो हो जाएगी। भारत अपनी 85 प्रतिशत पेट्रोलियम जरूरतों को आयात के जरिए पूरा करता है।

यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद कच्चे तेल की कीमतों में पिछले महीने से ही खासा उछाल देखा जा रहा है। बाजार के ?विशषज्ञों का कहना है ?कि कच्चे तेल के दाम 100-120 डॉलर प्रति बैरल के दायरे में रहने पर पेट्रोलियम कंपनियों को डीजल में प्रति लीटर 13.1-24.9 रुपए की बढ़ोतरी करने की जरूरत होगी जबकि पेट्रोल के मामले में यह वृद्धि 10.6-22.3 रुपए प्रति लीटर तक हो सकती है।

रक्षा निर्माण में आत्मनिर्भरता की दिशा में बढ़ा एक और कदम

रक्षा मंत्रालय ने रणनीतिक महत्व की 107 उप प्रणालियों का आयात रोका

नई दिल्ली । रक्षा मंत्रालय ने रक्षा निर्माण में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए 107 रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण लाइन रिप्लेसमेंट इकाइयों या उप प्रणालियों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। मंत्रालय ने कहा, 'रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करने के सतत प्रयास और 'आत्मनिर्भर भारत' के तहत रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (डीपीएसयू) द्वारा आयात कम करने के लिए रक्षा मंत्रालय ने समय सीमा के साथ 107 रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण लाइन रिप्लेसमेंट इकाइयों-उप प्रणालियों की दूसरी सूची को मंजूरी दी है। तय समय के बाद इनका आयात नहीं किया जाएगा।'

आने वाले वर्षरें में इन 107 उप प्रणालियों का स्वदेशीकरण किया जाएगा। सूची में उनमें से प्रत्येक के सामने बताई गई समय-सीमा के बाद भारतीय उद्योग से ही उनकी खरीद की जाएगी। डीपीएसयू द्वारा इन वस्तुओं का 'मेक' श्रेणी के तहत स्वदेशीकरण किया जाएगा। 'मेक' श्रेणी का उद्देश्य भारतीय उद्योगों की ज्यादा से ज्यादा भागीदारी के माध्यम से आत्मनिर्भरता हासिल करना है। उद्योग द्वारा उपकरणों, प्रणालियों, प्रमुख प्लेटफामरें या उनके अपग्रेड, डिजाइन एवं विकास से संबंधित प्रोजेक्ट को इस श्रेणी के तहत लिया जा सकेगा। उद्योग की अगुआई वाले डिजाइन और विकास के लिए पहचाने गए एलआरयू, उप-प्रणालियों की डीपीएसयू पेशकश करेगा। प्रमुख रक्षा प्लेटफामरें के निर्माण की आपूर्ति श्रृंखलाओं में यह भारतीय उद्योग के लिए एकीकृत होने का एक बड़ा अवसर होगा।

रक्षा मंत्रालय ने रक्षा निर्माण में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए एक और बड़ा फैसला लिया है। आइएएनएस के मुताबिक रक्षा मंत्रालय ने 107 रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण लाइन रिप्लेसमेंट इकाइयों या उप प्रणालियों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। वहीं समाचार एजेंसी एएनआइ की रिपोर्ट के मुताबिक यांगिआरिक में भव्य उद्घाटन समारोह के साथ भारत-उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास 'डस्टलिक' के तीसरे संस्करण की शुरुआत हुई। उद्घाटन समारोह के दौरान संयुक्त अभ्यास में भाग ले रहे दोनों देशों के राष्ट्रीय ध्वज फहराए गए और उसके बाद राष्ट्र गान के धुन बजाए गए। अभ्यास में भाग लेने के लिए भारतीय सेना का दस्ता मंगलवार को उज्बेकिस्तान पहुंचा।

यह संयुक्त अभ्यास संयुक्त राष्ट्र की भावना के तहत अर्ध शहरी क्षेत्रों में आतंकवाद विरोधी अभियानों पर केंद्रित रहेगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम मुख्य रूप से सामरिक स्तर के अभ्यासों को साझा करने और एक दूसरे से बेहतर सीखने पर केंद्रित होगा। अभ्यास का उद्देश्य दोनों सेनाओं के बीच समझदारी, सहयोग और पारस्परिकता को बढ़ाना है। उज्बेकिस्तान के यांगिआरिक में 22 मार्च से शुरू हुआ अभ्यास का तीसरा संस्करण 31 मार्च तक जारी रहेगा।

बीरभूम हिंसा पर बीजेपी ने ममता सरकार को घेरा

कलकत्ता (ईएमएस)। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में हुई हिंसा के बाद से सियासी पारा चढ़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) इसे पूरे मामले को लेकर राज्य की तृणमूल कांग्रेस सरकार पर हमलावर है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा और कहा कि इस घटना ने पूरे हिंदुस्तान को झकझोर दिया है। संबित पात्रा ने कहा कि ये सिर्फ बंगाल का मुद्दा नहीं है ये देश का मुद्दा है। कल पीएम ने भी इस मुद्दे पर खेद जताया है। ये बदले में की गई घटना है। ये देश के लिए बहुत चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को कमरे में बंद करके मार दिया जाता है। संबित पात्रा ने कहा किनआपका नाम तो ममता है, लेकिन आपका काम निर्मम है। आपका नाम निर्मम बनर्जी हैउन्होंने कहा कि पिछले एक हफ्ते में 26 लोगों की राजनीति हत्या हुई है, मुझे दुख है ममता बनर्जी को इनपर काम करके रोकना चाहिए , जिस गांव में महिला की हत्या हुई है पुलिस वहां से गायब थी। पुलिस सब जानते हुए भी वहां नहीं थी। पुलिस को कहीं से निर्देष दिया गया था, वहां नहीं पहुंचना है।

गुजरात और महाराष्ट्र को एक करने की बात कह वहां भी टाले जा सकते हैं चुनाव: केजरीवाल

नई दिल्ली (ईएमएस)। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली नगर निगमों के एकीकरण की आड़ में एमसीडी चुनाव टालने को लेकर केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा पर जमकर हमला बोला। केजरीवाल ने पूछा है कि क्या इस तरह और गुजरात या फिर लोकसभा के चुनाव भी टाले जा सकते हैं। केजरीवाल ने भाजपा के इस कदम को शहीदों का अपमान बताया है। केजरीवाल ने अपने एक फेसबुक पोस्ट में कहा है कि भाजपा का दिल्ली नगर निगम के चुनाव टालना शहीदों का अपमान है, जिन्होंने अंग्रेजों को देश से भगाकर देश में जनतंत्र स्थापित करने के लिए कुर्बानियां दीं थीं। आज ये हार के डर से दिल्ली नगर निगम के चुनाव टाल रहे हैं, कल ये राज्यों और देश के चुनाव टाल देंगे। भाजपा यह कहकर एमसीडी के चुनाव टाल रही है कि दिल्ली के तीनों निगम एक कर रहे हैं। क्या इस वजह से चुनाव टल सकते हैं? कल ये गुजरात हार रहे होंगे तो क्या ये कह कर टाल सकते हैं कि गुजरात और महाराष्ट्र को एक कर रहे हैं? क्या इसी तरह का कोई बहाना बनाकर लोकसभा चुनाव टाले जा सकते हैं?

भाजपा अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहती है। कमाल है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी एक छोटी सी आम आदमी पार्टी (आप) से घबरा के भाग गई? हिम्मत है तो एमसीडी के चुनाव टाइम पर करवा के दिखाओ। इसके साथ ही आज दिल्ली विधानसभा के बाहर मीडिया से बात करते हुए केजरीवाल ने कहा कि अगर भाजपा एमसीडी चुनावों को समय पर कराकर जीत हासिल करती है तो हम राजनीति छोड़ देंगे। दिल्ली के तीनों नगर निगमों को एक करने के बिल को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी मिलने के एक दिन बाद उन्होंने यह ऐलान किया है।

राज्यपाल धनखड़ को पद से हटाए मोदी सरकार टीएमसी सांसदों ने अमित शाह से मिलकर की मांग

कलकत्ता (ईएमएस)। सांसद सुदीप बंद्योपाध्याय के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के प्रतिनिधिमंडल ने संसद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और उनसे बीरभूम की घटना को देखते हुए पश्चिम बंगाल के राज्यपाल को हटाने का आग्रह किया। डेरेक ओ ब्रायन, महुआ मोइत्रा और अन्य नेताओं सहित टीएमसी प्रतिनिधिमंडल ने शाह से मुलाकात की। बंद्योपाध्याय ने अमित शाह से मुलाकात के बाद कहा, ठहमने कहा है कि रामपुरहाट, बीरभूम की घटना को देखते हुए पश्चिम बंगाल के राज्यपाल को हटाया जाना चाहिए। उनका काम हमारी संवैधानिक व्यवस्था के खिलाफ है। संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था खतरे में है। उन्होंने आगे बताया कि घटना में अब तक 21 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बंद्योपाध्याय ने कहा, ठहमने राज्यपाल बदलने के लिए मुख्यमंत्री के पत्र की एक प्रति गृह मंत्री को दी है। हमारी मुख्यमंत्री स्थिति को अच्छी तरह से संभाल रही हैं। अब तक 21 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, 15 पुलिस अधिकारियों को छुट्टी पर जाने के लिए कहा गया है। किसी भी दोषी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। यह पूछे जाने पर कि गृह मंत्री ने क्या कहा, टीएमसी सांसद ने कहा, ठउन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि हम इस मामले में किसी राजनीतिक एंगल की तलाश नहीं कर रहे हैं। मेरा यह भी मानना है कि इस घटना में मेरा कोई राजनीतिक एंगल नहीं है। पश्चिम बंगाल के बीरभूम के रामपुरहाट इलाके में द्वारा घरों में आग लगाने के बाद कुल आठ लोगों की मौत हो गई। बनर्जी के रामपुरहाट दौरे से पहले बीरभूम के पुलिस अधीक्षक नागेंद्र नाथ त्रिपाठी ने पुलिस कर्मियों के एक बड़े दल के साथ गांव का निरीक्षण किया। वहीं कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद रामपुरहाट के हिंसा प्रभावित इलाके में सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। रामपुरहाट की घटना पर स्वतः संज्ञान लेते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बुधवार को राज्य सरकार को चौबीसों घंटे निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने राज्य सरकार को 24 घंटे में (गुरुवार दोपहर करीब 2 बजे तक) घटना पर स्थिति रिपोर्ट देने का भी निर्देश दिया है। मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल का गठन किया गया है।

मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक के आरोपों की होगी सीबीआई जांच?

-300 करोड़ की घूस के दावे पर की गई सिफारिश

जम्मू (ईएमएस)। मेघालय के वर्तमान राज्यपाल सत्यपाल मलिक अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में बने रहते हैं। इससे पहले जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने पिछले दिनों दावा किया था कि आरएसएस से जुड़े एक नेता और अंबानी से जुड़ी फाइलों को मंजूरी के एवज में उन्हें 300 करोड़ रुपये की घूस का प्रस्ताव किया गया था। सत्यपाल मलिक के इस दावे से सनसनी फैल गई थी। अब जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने उनके इन आरोपों की सीबीआई से जांच कराने की सिफारिश कर दी है। सत्यपाल मलिक का कहना था कि फाइल करने के लिए उन्हें 300 करोड़ रुपये ऑफर किए गए थे, लेकिन उन्होंने यह डील ही निरस्त कर दी थी। हालांकि इस दौरान मलिक ने पीएम नरेंद्र मोदी की सराहना करते हुए कहा था कि उस वक्त पीएम ने उनसे कहा था कि वह भ्रष्टाचार से कोई समझौता ना करें।

राजस्थान में आयोजित एक कार्यक्रम में मलिक ने ये दावे किए थे। उन्होंने कहा था, 'कश्मीर जाने के बाद मेरे पास दो फाइलें आईं। एक अंबानी की फाइल थी और दूसरी आरएसएस से जुड़े एक शख्स की थी जो पिछली महबूबा मुफ्ती और बीजेपी की गठबंधन सरकार में मंत्री थे। वह पीएम मोदी के भी बेहद करीबी थे।' मलिक ने आगे कहा, 'मुझे सचिवों ने सूचना दी कि इसमें घोटाला है और फिर मैंने बारी-बारी से दोनों डील रद्द कर दीं। सचिवों ने मुझसे कहा कि दोनों फाइलों के लिए 150-150 करोड़ रुपये दिये जाएंगे। लेकिन मैंने उनसे कहा कि मैं पांच कुर्ता-पायजामे के साथ आया हूं और सिर्फ उसी के साथ यहां से चला जाऊंगा।'

सत्यपाल मलिक पहले भी जम्मू-कश्मीर को लेकर कई दावे कर चुके हैं। उन्होंने कहा था कि जम्मू-कश्मीर देश के सबसे भ्रष्ट राज्यों में से एक है। मलिक ने कहा था कि देश में कश्मीर सबसे भ्रष्ट स्थान है। पूरे देश में चार से पांच फीसदी कमीशन मांगा जाता है, लेकिन कश्मीर में 15 फीसदी की मांग की जाती है। उन्होंने कहा कि उनके रहते हुए कश्मीर में भ्रष्टाचार को कोई बड़ा केस सामने नहीं आया। उन्होंने कहा, 'चूंकि मैं गरीब आदमी हूं, इसलिए देश के किसी भी ताकतवर आदमी से लड़ सकता हूं। रिटायर होने के बाद रहने के लिए घर भी नहीं है, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है।

सत्यपाल मलिक फिलहाल मेघालय के राज्यपाल हैं, लेकिन संवैधानिक पद पर रहते हुए भी अकसर वह राजनीतिक मुद्दों पर खुलकर बोलते रहे हैं। किसान आंदोलन के दौरान उन्होंने सरकार को असहज करने वाली भी कई टिप्पणियां की थी। यहां तक कि उन्होंने यह भी दावा किया था कि किसानों के मरने पर पीएम नरेंद्र मोदी ने उनसे कहा था कि क्या वे मेरे लिए मरे हैं। सत्यपाल मलिक कई बार सरकार की कृषि कानूनों को लेकर आलोचना कर चुके हैं।

पाबंदियां हटते ही बढ़ने लगा कोरोना, दैनिक मामले और मौत के आंकड़ों में होने लगी बढ़ोतरी

नई दिल्ली (ईएमएस) महामारी कोरोना के लंबे अंतराल के बाद भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने 31 मार्च से केविड-19 को लेकर जारी सभी पाबंदियों को समाप्त कर दिया। हालांकि, मास्क पहनने को लेकर अनिवार्यता बनी रहेगी। हाल के कुछ दिनों के आंकड़ों पर गौर करें तो अचानक से मामले बढ़ रहे हैं। आपको बता दें कि बीते तीन दिनों में दैनिक मामलों में 350 के करीब इजाफा हुआ है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक, 24 मार्च को 1938 नए केस सामने आए हैं। इसके साथ ही 23 मार्च को 1778 नए मामले सामने आए थे। सबसे कम 21 मार्च को नए दैनिक केस सामने आए थे। इस दिन 1549 मामलों की पुष्टि हुई थी। आपको बता दें कि 22 मार्च को 1581 और 20 मार्च को 1761 नए मामलों की पुष्टि हुई थी। कोरोना के नए मामलों में तो इजाफा हुआ ही है, साथ ही मौत के आंकड़ों में भी उछाल देखने को मिला है। आपको बता दें कि 20 मार्च को 127 मरीजों की कोरोना से मौत हुई थी। उसके बाद दो दिनों तक रोज 33-33 मरीजों की जान गई। वहीं, 23 मार्च को 62 मौत रिकॉर्ड किए गए। साथ ही 24 मार्च को 67 मरीजों की मौत हो गई।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक, भारत में एक दिन में कोविड-19 के 1,938 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 4,30,14,687 हो गई। वहीं, 67 और लोगों की संक्रमण से मौत के बाद मृतक संख्या बढ़कर 5,16,672 हो गई देश में कोविड-19 के उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 22,427 हो गई है। केरल में बुधवार को कोरोना वायरस (कोविड-19) महामारी के 702 नए मामले सामने है और इस दौरान दो मरीजों की मौत हुई है। आज यहां जारी आधिकारिक बयान के अनुसार पिछले 24 घंटे में 23,238 लोगों के नमूनों की जांच के बाद आज 702 नये मामलों की पुष्टि हुई। उन्होंने बताया कि इस बीच रिकॉर्ड के अभाव में हाल ही में हुई छह मौतों को आज जोड़ा गया है। इसके साथ ही राज्य में इस बीमारी से मरने वालों की संख्या को 67,476 हो गई है।

कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में भारी कमी आने के चलते केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड की रोकथाम के लिए उठाए गए सभी कदमों को समाप्त करने का फैसला किया है। हालांकि, केंद्र ने बुधवार को स्पष्ट किया कि मास्क का उपयोग और हाथों की लगातार सफाई जैसे उपाय जारी रहेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि मास्क पहनने और हाथ स्वच्छ रखने में छूट देने की बात कहने वाली खबरें ''असत्य'' हैं। मंत्रालय ने ट्वीट किया, 'मीडिया में आई कुछ खबरों में कहा गया है कि मास्क पहनने और हाथ स्वच्छ रखने के प्रोटोकॉल में छूट दी गई है। वे असत्य हैं। फेस मास्क का उपयोग और हाथों की सफाई जैसे उपाय जारी रहेंगे।'

केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को लिखे एक पत्र में कहा है कि मास्क के उपयोग और हाथ स्वच्छ रखने सहित कोविड रोकथाम उपायों पर परामर्श महामारी के खिलाफ संपूर्ण राष्ट्रीय अभियान में प्रमुखता से रहेंगे। भल्ला ने पत्र में कहा है कि पिछले 24 महीने में, निदान, निगरानी, संपर्क का पता लगाना, उपचार, टीकाकरण, अस्पताल का बुनियादी ढांचा जैसे महामारी प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं के लिए कई महत्वपूर्ण क्षमताएं विकसित की गई हैं। उन्होंने कहा कि इसके अलावा अब आम लोगों में कोविड उपयुक्त व्यवहार के बारे में उच्च स्तर की जागरूकता है। पत्र में कहा गया है, 'स्थिति में हुए संपूर्ण सुधार और महामारी से निपटने के लिए सरकार की तैयारियों पर विचार करते हुए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने यह फैसला किया है कि कोविड रोकथाम उपायों के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम के प्रावधानों को आगे लागू रखने की जरूरत नहीं है।' भल्ला ने कहा कि मौजूदा आदेश के 31 मार्च को निष्प्रभावी होने के बाद गृह मंत्रालय आगे कोई आदेश जारी नहीं करेगा।

यूएनओ में उठी मांग, क्या अब पीओके की तरह अक्साई चिन भी कहलाएगा सीओके

जिनेवा (ईएमएस)। जिनेवा स्थित यूएनओ के संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 49वें सत्र के दौरान एक कश्मीरी बुद्धिजीवी और मानवाधिकार कार्यकर्ता ने बीजिंग द्वारा अक्साई चिन पर अवैध कब्जे का मुद्दा उठाया जिससे चीन को मिर्ची लग गई है। ब्रसेल्स स्थित यूरोपीय फाउंडेशन फॉर साउथ एशियन स्टडीज के निदेशक औक श्रीनगर के कश्मीरी जुनैद कुरैशी ने संयुक्त राष्ट्र के सामने बीजिंग के अवैध कब्जे वाले क्षेत्र को चीन के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर शब्द को औपचारिक रूप देने का आह्वान किया।

जुनैद ने कहा कि अक्साई चिन जम्मू और कश्मीर के 20 प्रतिशत से अधिक क्षेत्र में शामिल है और लगभग भूटान के समान आकार का है। जम्मू और कश्मीर मुद्दे पर मौजूदा शब्दावली के आधार पर, संयुक्त राष्ट्र और उसके यूएनएचआरसी जैसे विभिन्न अंगों से ने चीन द्वारा क्षेत्र के बड़े हिस्से पर अवैध कब्जे की पूरी तरह से अनदेखी की है। उन्होंने कहा कि इस चूक का गंभीर प्रभाव पड़ा है। उस लिहाज से इस तरह की चूक का गंभीर प्रभाव पड़ा है।

चीन ने जुनैद की इस मांग का विरोध किया है। इस बयान को चीन की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता के खिलाफ बताया है। बता दें कि 1950 के दशक के दौरान चीन ने अक्साई चिन (लगभग 38,000 वर्ग किमी क्षेत्र) पर कब्जा कर लिया और 1962 के भारत-चीन युद्ध के दौरान इस क्षेत्र पर अपनी सैन्य पकड़ मजबूत कर ली। यह क्षेत्र दोनों देशों के बीच विवाद का विषय बना रहा।

योगी आदित्यनाथ को औपचारिक रूप से विधायक दल का नेता चुना गया

लखनऊ (ईएमएस)। उत्तरप्रदेश के बीजेपी विधायकों की बैठक में आज योगी आदित्यनाथ को औपचारिक रूप से विधायक दल का नेता चुना गया। योगी लगातार दूसरी बार शुक्रवार को यूपी के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। अपने संबोधन में योगी ने लोगों को याद दिया कि यह पहली बार है जब किसी सीएम को राज्य में लगातार दूसरा कार्यकाल मिल रहा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने दिखाया है कि चुनावों को राष्ट्रवाद और सुशासन के मुद्दे पर लड़ा जा सकता है। यूपी में हाल ही में हुए चुनावों में बीजेपी ने लगातार दूसरी बार सत्ता में वापसी की है, करीब चार दशक बाद ऐसा हुआ हुआ कि कोई पार्टी कार्यकाल पूरा करने के बाद यूपी में फिर सत्ता में आई है।

योगी ने कहा, 'पार्टी ने वर्ष 2017 में मुझमें विश्वास जताया था। उस समय मैं केवल सांसद था और मुझे प्रशासनिक अनुभव नहीं था। ऐसे में पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री मेरे लिए संरक्षक की तरह थे। इन्होंने मुझे बताया कि यूपी के लिए सुशासन कैसे किया जाए ' गोरखपुर से पांच बार सांसद रहे योगी ने कहा, 'एक सांसद के रूपमें आप कुछ चीजें जान सकते हैं लेकिन शासन और प्रशासन कैसे किया जाता है, यह इससे अलग बात हैं। उन्होंने कहा, 'एक सांसद होने का सीमित दायरा है लेकिन यूपी जैसे राज्य पर शासन करना अलग बात हैं और मिले मार्गदर्शन के कारण हम यूपी में सुशासन की दिशा में कामयाब रहे।'योगी आदित्यनाथ ने कहा, 'विपक्ष और ऐसे लोग, जो देश को अस्थिर करना चाहते हैं तो इन चुनाव के नतीजों को प्रभावित करने की पूरी कोशिश की लेकिन पीएम के नेतृत्व में हमने दिखाया है कि चुनाव को राष्ट्रवाद और सुशासन के मुद्दे पर लड़ा जा सकता है। 'बीजेपी विधायक दल की बैठक में पर्यवेक्षक केंद्रीय पार्टी गृह मंत्री अमित शाह और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुबर दास मौजूद थे।बीजेपी विधायक दल की बैठक खत्म हो चुकी है। राज्यपाल आनंदीबेन से मिलकर योगी आदित्यनाथ सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे।

बैठक में मनोनीत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश पार्टी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राधा मोहन सिंह, पूर्व उपमुख्यमंत्री दिनेश शर्मा और केपी मौर्य भी मौजूद रहे। वहीं पार्टी सूत्रों का कहना है कि दो उपमुख्यमंत्रियों को बरकरार रखा जा सकता है। बता दें कि योगी आदित्यनाथ कल लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए यूपी के मुख्यमंत्री के रूप में संभवतः 45 मंत्रियों के साथ शपथ लेंगे। सूत्रों ने उक्त बात की जानकारी दी है। इससे पहले योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को शपथ ग्रहण समारोह से पहले अपने मंत्रिमंडल के लिए नामों को अंतिम रूप देने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की थी। सूत्रों ने कहा कि यूपी में योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैबिनेट के नामों पर ठपूरी तरह से सहमतठ हैं।

हैती में 5.1 तीव्रता वाला भूकंप आया, कुछ लोग घायल

पोर्ट ऑ प्रिंस (ईएमएस)। हैती में बुधवार को 5.1 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। जेरमी में 'रेडियो कैराबेस' के एक रिपोर्टर ने को बताया कि भूकंप के कारण अभी तक किसी के मारे जाने या गंभीर रूप से घायल होने की कोई जानकारी नहीं है।

भूकंप महसूस होने पर लोग घबरा कर भागने लगे जिससे कुछ लोग मामूली रूप से घायल हुए हैं। कुछ लोगों ने बताया कि 2021 में आए भूकंप से जिन दीवारों में दरारें आ गईं थी, वे ढह गईं। हैती की नागरिक सुरक्षा एजेंसी के प्रवक्ता से तत्काल संपर्क नहीं हो सका। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने बताया कि भूकंप का केन्द्र जेरेमी से 11 मील (18 किलोमीटर) उत्तर में, छह मील (10 किलोमीटर) की गहराई पर था। अगस्त 2021 में दक्षिणी हैती में 7.2 तीव्रता का भीषण भूकंप आया था, जिसमें 2000 से अधिक लोग मारे गए थे और हजारों मकान क्षतिग्रस्त हो गए थे।

बीरभूम में जिंदा जलाने से पहले बुरी तरह पीटे गए थे लोग

-बोगतुई गांव में मारे गए लोगों की पोस्टमार्टम जांच में हुआ खुलासा

-पश्चिम बंगाल सरकार ने घटना की जांच के लिए एसआईटी गठित की

कोलकाता(ईएमएस)। बीरभूम कांड में एक बेहद ही सनसनीखेज खुलासा हुआ है। फोरेंसिक विशेषज्ञों की रिपोर्ट में कहा गया है कि बंगाल के बीरभूम जिले के बोगतुई गांव में जिंदा जलाए गए तीन महिलाओं और दो बच्चों समेत आठ लोगों को नरसंहार से पहले बुरी तरह पीटा गया था। उनकी पोस्टमार्टम जांच में यह खुलासा हुआ है। एक अधिकारी ने रामपुरहाट अस्पताल से बताया कि फोरेंसिक विशेषज्ञों के शुरुआती निष्कर्षों के अनुसार, पीड़ितों को पहले बुरी तरह पीटा गया और फिर जिंदा जला दिया गया। फोरेंसिक विशेषज्ञों ने मंगलवार तड़के अज्ञात लोगों द्वारा कथित तौर पर आग लगाकर जला दिए गए लोगों के शवों का परीक्षण किया था। घटना के संबंध में अब तक कम से कम 20 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। रामपुरहाट के बोगतुई गांव में मंगलवार को तड़के करीब एक दर्जन मकानों में कथित तौर पर आग लगा देने से दो बच्चों समेत कुल आठ लोगों की जलकर मौत हो गयी। यह घटना टीएमसी के पंचायत स्तर के नेता भादू शेख की कथित हत्या के कुछ घंटों के भीतर हुई। तृणमूल कांग्रेस के नेता की हत्या के बाद रामपुरहाट शहर के बाहरी इलाके में स्थित बोगतुई गांव में करीब एक दर्जन मकानों पर कथित तौर पर पेट्रोल बम से हमला कर आग लगा दी गई थी। ऐसा कहा जा रहा है कि कुछ लोगों ने अपने नेता की हत्या के प्रतिशोध में मकानों में आग लगा दी। पुलिस ने इस सिलसिले में अब तक कम से कम 20 लोगों को गिरफ्तार किया है। राज्य सरकार ने कथित रूप से लापरवाही बरतने के आरोप में कई प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निर्धारित दौरे के दौरान कोई अप्रिय घटना न हो इसके लिए रामपुरहाट में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि हेलीपैड के आसपास सीसीटीवी लगाए गए हैं, जहां मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर उतरेगा। ब

जन हितैषी

धामी की चुनौतियां

उत्तराखंड के 12वें मुख्यमंत्री के रूप में पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को शपथ ली। देहरादून के परेड ग्राउंड में गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (रिटायर्ड) उन्हें मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। सत्ता की कमान संभालने के साथ ही धामी के सामने चुनौतियां भी कम नहीं हैं। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने के साथ ही धामी को विधायक बनने से लेकर चुनाव में किए गए वादों को पूरा करना और वरिष्ठ नेताओं के साथ संतुलन बनाने की चुनौतियां से सामना करना होगा। पुष्कर सिंह धामी के सामने सबसे पहली चुनौती उपचुनाव की होगी। मुख्यमंत्री के पद पर बने रहने के लिए उन्हें किसी भी सूरत में उपचुनाव जीतना होगा। मुख्यमंत्री के तौर पर धामी के सामने सबसे बड़ी चुनौती वरिष्ठ नेताओं के साथ संतुलन बनाने की चुनौती होगी। धामी के पहले छह महीने के कार्यकाल में कई वरिष्ठ नेताओं के साथ लेकर नहीं चल सके, जिसके चलते हरक सिंह रावत से लेकर यशपाल आर्य जैसे नेता पार्टी छोड़ गए। इसके अलावा कई नेताओं की नाराजगी की बातें सामने आई थीं। सरकार बनने के बाद पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, विधायकों को साथ लेकर चलने के लिए धामी को अपना राजनीतिक कौशल दिखाना होगा। पुष्कर सिंह धामी के सामने चुनावी वादों को पूरा करने की चुनौती होगी। उत्तराखंड चुनाव के दौरान पार्टी ने तमाम बड़े वादे किए हैं, जिन्हें अमलीजामा पहनाने का जिम्मा धामी के कंधों पर होगा। लव जिहाद कानून को और कठोर बनाना, समान नागरिक संहिता, भू कानून, जनसंख्या नियंत्रण सरीखे वादों को भी पूरा करने का दबाव रहेगा। इसके अलावा किसानों के खाते में 12 हजार रुपए देने का वादा है। गरीब घरों को साल में तीन सिलेंडर निशुल्क और बीपीएल परिवार की महिलाओं को 2000 प्रतिमाह, गरीब बच्चों को एक हजार प्रति माह देने जैसे लोकलुभाने वादे हैं। इन्हें सत्ता पर काबिज होते ही पूरा करने की चुनौती होगी। धामी मुख्यमंत्री की भूमिका में अपनी छोटी लेकिन तेजतर्रार पारी खेली है। धामी ने अपने पिछले छह महीने के कार्यकाल में नौकरशाही पर लगाम कसने की कोशिश की। उनकी एक कुशल प्रशासक की छवि बनी भी। अब पार्टी ने उन्हें पांच साल के लिए सत्ता की कमान सौंपी है। ऐसे में उन्हें नौकरशाही पर अंकुश लगाना होगा। उत्तराखंड में माना जाता रहा है कि नौकरशाही कभी सरकार के नियंत्रण में नहीं रही। पिछली सरकार में तमाम मंत्री अफसरों के सामने अपनी लाचारी की पीड़ा सार्वजनिक रूप से जाहिर करते रहे हैं। केंद्रीय नेतृत्व ने जिस तरह से पुष्कर सिंह धामी को चुनाव हारने के बावजूद सत्ता की कमान सौंपी है, उससे उनकी चुनौती और जिम्मेदारी बढ़ गई है। अब केंद्रीय नेतृत्व की उम्मीदों पर खरा उतरने की चुनौती होगी। पीएम नरेंद्र मोदी ऐलान कर चुके हैं कि अगला दशक उत्तराखंड का होगा। 2025 तक उत्तराखंड आदर्श राज्य होगा। मोदी के इस विजन को जमीन पर उतारने की चुनौती धामी के सामने है। इसके बाद शहरी निकाय चुनाव, फिर 2024 का लोकसभा चुनाव की चुनौती धामी के सामने होगी। पिछले दो लोकसभा चुनाव से बीजेपी क्लीन स्वीप कर रही है, जिसे 2024 में बरकरार रखना होगा। लोकसभा के लिए महज दो साल का ही वक्त धामी के सामने होगा। पुष्कर सिंह धामी दूसरी बार सत्ता की कमान संभालकर सियासी इतिहास रचने जा रहे हैं, लेकिन चुनौती पांच साल के सफर को तय करने की है। उत्तराखंड के 20 साल के इस सफर में प्रदेश को 11 मुख्यमंत्री मिले हैं और धामी 12वें सीएम। भाजपा ने सात मुख्यमंत्री दिए हैं, तो कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश को तीन मुख्यमंत्री दिए हैं। सूबे के सभी मुख्यमंत्रियों में से सिर्फ कांग्रेस नारायण दत्त तिवारी ही अपना पांच साल का कार्यकाल पूरा कर पाए थे जबकि भाजपा का कोई नेता पांच साल तक सीएम नहीं रहा सका। भाजपा ने पिछले कार्यकाल में दो सीएम बदले हैं। राज्य की अर्थव्यवस्था संतोषजनक स्थिति में नहीं है। आय के साधन न होने की वजह से राज्य पर इस वक्त 65 हजार करोड़ रुपए का कर्ज हो चुका है। हालत यह है कि कार्मिकों के वेतन के लिए अक्सर सरकार को बाजार से कर्ज लेना पड़ता है। कर्ज का ब्याज चुकाने के लिए राज्य को नया कर्ज लेना पड़ता है। आर्थिक स्थिति को पटरी पर लाने के लिए आय के नए स्रोत तलाशने होंगे। पलायन राज्य की बड़ी समस्याओं में शामिल है। रोजगार के अभाव में लोगों को शहरों और दूसरे राज्यों को पलायन करना पड़ रहा है। वर्ष 2011 तक राज्य के 968 गांव खाली हो गए थे। वर्ष 2011 के बाद इनमें 734 गांव और जुड़ चुके हैं। सीमांत क्षेत्रों के विकास के लिए ठोस योजनाएं न होने की वजह से पलायन का सिलसिला लगातार जारी है। कोरोना काल में लौटे प्रवासियों में भी ज्यादातर इसी वजह से वापस लौट चुके हैं।

हिजाब प्रकरण : अलग दिखने की जिद क्यों ?

भारत एक लोकतांत्रिक देश है। यहां सभी धर्मों और संप्रदायों के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं। सभी को अपने-अपने धर्म के अनुसार धार्मिक कार्य करने एवं जीवन यापन करने का अधिकार प्राप्त है। परन्तु कुछ अलगाववादी शक्तियों के कारण देश में किसी न किसी बात को लेकर प्रायः विवाद होते रहते हैं। इन विवादों के कारण जहां शान्ति का वातावरण अशांत हो जाता है, वहीं लोगों में मनमुटाव भी बढ़ जाता है। ताजा उदाहरण है हिजाब प्रकरण। कर्नाटक के उडुपी से प्रारंभ हुआ हिजाब प्रकरण थमने का नाम ही नहीं ले रहा है।

मंगलवार को कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध लगाने को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं को खारिज कर दिए जाने के पश्चात यह मामला अब सर्वोच्च न्यायालय पहुंच गया है। कर्नाटक उच्च न्यायालय का कहना है कि छात्रों को स्कूलों में हिजाब नहीं, यूनिफॉर्म पहननी होगी। न्यायालय का कहना है कि हिजाब पहनना इस्लाम की अनिवार्य धार्मिक प्रथा नहीं है। हिजाब मामले में राज्य के एडवोकेट जनरल प्रभुलिंग नवादगी ने कर्नाटक उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ के सामने सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि हिजाब इस्लाम का अनिवार्य अंग नहीं है और इसके उपयोग पर रोक लगाना संविधान के अनुच्छेद 25 का उल्लंघन नहीं है। उन्होंने कहा कि हिजाब धर्म के पालन के अधिकार के अंतर्गत दिखावे का भाग है। पूर्ण पीठ में न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी, न्यायाधीश जेएम काजी एवं न्यायाधीश कृष्णा एम दीक्षित सम्मिलित हैं। एडवोकेट जनरल ने कहा कि सरकार का आदेश संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) का उल्लंघन भी नहीं करता। यह अनुच्छेद भारतीय नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। उन्होंने यह भी कहा कि यूनिफॉर्म के बारे में सरकार का आदेश पूरी तरह शिक्षा के अधिकार कानून के अनुरूप है और इसमें कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है। उन्होंने कहा कि उडुपी के सरकारी प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज में यूनिफॉर्म का नियम वर्ष 2018 से लागू है, परन्तु समस्या तब प्रारंभ हुई जब विगत दिसंबर में कुछ छात्राओं ने प्राचार्य से हिजाब पहनकर कक्षा में जाने की अनुमति मांगी। इस पर उनके अभिभावकों को कॉलेज में बुलाया गया और यूनिफॉर्म लागू होने की बात कही गई, परन्तु छात्राएं नहीं मानीं और उन्होंने विरोध आरंभ कर दिया। जब मामला सरकार के संज्ञान में आया, तो उसने मामले को तूल न देने की अपील करते हुए एक उच्च स्तरीय समिति बनाने की बात कही। किन्तु छात्राओं पर इसका कोई प्रभाव नहीं हुआ। जब मामला बढ़ गया, तो सरकार ने 5 फरवरी को आदेश देकर ऐसे किसी भी वस्त्र को पहनने से मना कर दिया, जिससे शांति, सौहार्द्र एवं कानून व्यवस्था प्रभावित हो रही हो।

विशेष बात यह भी है कि उच्च न्यायालय ने पर्दा प्रथा पर भीमराव आंबेडकर की टिप्पणी का भी का उल्लेख करते हुए कहा- ठपर्दा, हिजाब जैसी चीजें किसी भी समुदाय में हों तो उस पर बहस हो सकती है। इससे महिलाओं की आजादी प्रभावित होती है। यह संविधान की उस भावना के विरुद्ध है, जो सभी को समान अवसर प्रदान करने, सार्वजनिक जीवन में हिस्सा लेने और पॉजिटिव सेक्युलरिज्म की बात करती है।''

भारत में व्याप्त अनेक कुप्रथाओं ने महिलाओं को उनके मौलिक अधिकारों से वंचित रखा है। पर्दा प्रथा भी उनमें से एक है। इस प्रथा के कारण महिलाओं को अनेक समस्याओं से जूझना पड़ा। उन्हें घर की चारदीवारी तक सीमित कर दिया गया। पुनर्जागरण के युग में समाज सुधारकों ने इन कुप्रथाओं के विरोध में जनजागरण आन्दोलन चलाया। इसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिले। समय के साथ-साथ समाज में परिवर्तन आया। हिन्दू व अन्य समुदायों के साथ-साथ मुसलमान भी अपनी बच्चियों को स्कूल भेजने लगे, परन्तु उनका अनुपात अन्य समुदायों की तुलना में बहुत ही कम है, जो चिंता का विषय है। देश में सबको समान रूप से अधिकार दिए गए हैं। शिक्षण संस्थानों में भी सबके साथ समानता का व्यवहार किया जाता है। प्रश्न यह है कि कुछ लोग स्वयं को दूसरों से पृथक क्यों रखना चाहते हैं?

वास्तव में हिजाब प्रकरण मुस्लिम समाज की लड़कियों को शिक्षा से दूर रखने का एक षडयंत्र है। चूंकि शिक्षा ही मनुष्य को अज्ञानता के अंधकार से निकाल कर ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाती है, इसलिए रूढ़िवादी मानसिकता के लोग महिलाओं को शिक्षा से वंचित रखने के लिए ऐसे षडयंत्र रचते रहते हैं, ताकि वे अपने अधिकारों के लिए आवाज न उठा सकें। मुस्लिम समाज में महिलाओं की जो स्थिति है, वह किसी से छिपी नहीं है। जब मुस्लिम बहन-बेटियों के हक में भाजपा सरकार 'तीन तलाक' पर रोक लगाने का कानून लाई थी, तो शिक्षित और जागरूक मुस्लिम महिलाओं ने इसका खुले दिल से स्वागत किया था। उस समय भी रूढ़िवादी लोगों ने जमकर इसका विरोध किया था, परन्तु उनकी एक न चली। इस कानून ने मुस्लिम महिलाओं के जीवन को बेहतर बनाने का कार्य किया। अब कोई भी व्यक्ति 'तीन तलाक' कहकर अपनी पत्नी को घर से नहीं निकाल सकता। ऐसा करने पर उसे दंड दिए जाने का प्रावधान है।

उल्लेखनीय है कि यूरोप के अनेक देशों ने हिजाब अर्थात बुर्का पहनने पर आंशिक या पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया हुआ है, जिसमें ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड एवं स्विट्जरलैंड आदि सम्मिलित हैं। इटली और श्रीलंका में भी बुर्का पहनने पर प्रतिबंध है। इन सभी देशों में आदेश का उल्लंघन करने पर भारी आर्थिक दंड दिए जाने का प्रावधान है।

कुछ लोग हिजाब के मामले में कुरआन की दुहाई देते हुए कहते हैं कि इसमें कई स्थान पर हिजाब का उल्लेख किया गया है, परन्तु वे इस बात पर चुप्पी साध लेते हैं कि ड्रेस कोड के संदर्भ में ऐसा कुछ नहीं कहा गया। इस्लाम के पांच मूलभूत सिद्धांतों में भी हिजाब सम्मिलित नहीं है। वास्तव में धर्म का संबंध आस्था एवं विश्वास से होता है, जबकि वस्त्रों का संबंध क्षेत्र विशेष एवं आवश्यकताओं से होता है। उदाहरण के लिए किसी भी ठंडे स्थान पर रहने वाले लोग जो भारी भरकम गर्म वस्त्र पहनते हैं, वे किसी गर्म क्षेत्र में रहने वाले लोग नहीं पहन सकते। ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि भारत में कहीं भी हिजाब अथवा बुर्का पहनने पर कोई प्रतिबंध नहीं है, परन्तु जिन संस्थानों में ड्रेस कोड लागू है, वहां हिजाब पहनने की जिद क्यों की जा रही है? (लेखक-डॉ. सौरभ मालवीय/ईएमएस)

चिकित्सा शिक्षा को सस्ती एवं व्यवहारिक बनाये सरकार

-यूक्रेन जैसे देशों से सबक ले भारत सरकार

यूक्रेन की लड़ाई ने भारत के मेडिकल एजुकेशन सिस्टम को सारी दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया है। यूक्रेन से लौटते हजारों मेडिकल छात्रों ने भारत की मेडिकल शिक्षा की हकीकत बयान कर दी है। अकेले यूक्रेन की बात नहीं है बल्कि दुनिया के अनेक देशों में भारतीय छात्र मेडिकल शिक्षा लेने जाते हैं जिनकी संख्या लाखों में है। जब चीन में कोरोना फैला था। उस समय भी चीन के वुहान शहर सहित तमाम शहरों से बड़ी संख्या में मेडिकल छात्र भारत लौटे थे। रूस, कैरेबियन देश, ऑस्ट्रेलिया अमेरिका और ब्रिटेन सहित कई देशों में भारत के छात्र मेडिकल शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं। इन देशों में ना केवल इन छात्रों को मेडिकल शिक्षा भारत की अपेक्षा सस्ती दर पर मिलती है बल्कि सीटों की कमी भी नहीं रहती। आखिर क्या कारण है कि भारत में मेडिकल शिक्षा के प्रति छात्रों का रुझान होने तथा देश में डाक्टरों की भारी कमी के बावजूद भारत सरकार छात्रों को शिक्षित नहीं कर पा रही है।

भारत में प्रतिवर्ष लगभग 10 लाख छात्र डॉक्टर बनने के लिए मेडिकल एग्जामिनेशन नीट परीक्षा में बैठते हैं। इनमें से बमुश्किल 70 हजार छात्रों को एडमिशन मिल पाता है इसमें भी एनआरआई कोटा शामिल है। मेडिकल कालेज शुरु करने की भारी लागत विशेषज्ञ डाक्टरों की कमी तथा महंगी पढ़ाई, सीटों की कम संख्या और छात्रों की अधिकता से चिकित्सा शिक्षा मेडिकल क्षेत्र में भारी भ्रष्टाचार एवं कुप्रबंधन का बड़ा का कारण है।

भारत में कैसे बनता है मेडिकल कॉलेज

भारत में मेडिकल कॉलेज की लागत 400 करोड़ रुपए है। इतनी राशि का निवेश करना और तथा पढ़ाई का खर्च निकालना आसान नहीं है। मेडिकल एजुकेशन को लेकर सरकार के नियम और शर्तें बहुत सख्त हैं। सीटों के आवंटन से लेकर हर प्रक्रिया में अनेक बाधाएं हैं। सरकार ने मेडिकल ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की फीस भी तय कर दी है। 400 करोड़ खर्च करने के बाद भी प्रतिवर्ष करोणों के घाटे में कालेज और अस्पताल चलाने का जोखिम कोई नहीं उठाना चाहता। यही कारण है कि मेडिकल कॉलेज खोलने के प्रति निवेशकों की रुचि नहीं है। इसके विपरीत विदेशों में मेडिकल कॉलेज की लागत पढ़ाई और अस्पताल संचालन के नियम काफी सस्ता है।

कैरेबियन देशों में तो 50 हजार स्क्वायर फीट जमीन में मेडिकल कॉलेज खुल जाता है। जहां पर अमेरिका जैसे देशों के लिए योग्य चिकित्सक तैयार किए जाते हैं। वहां पर ऐसे 35 कॉलेज अमेरिका के लिए डॉक्टर तैयार कर रहे हैं। भारत में 200 छात्रों को प्रशिक्षित करने के लिए 140 फैकल्टी की आवश्यकता होती है। जबकि इन देशों में भारत की तुलना में मात्र 20 फीसदी फैकल्टी पढ़ाने के लिए जरुरी होती है। दुनिया के साथ भारत ने कदमताल करना नहीं सीखा। इसी कारण भारत में मेडिकल एजुकेशन एवं डाक्टर विलासिता और मोटी कमाई के प्रतीक बन गए हैं। जिसकी जेब में भरपूर पैसा हो वही डॉक्टर बन सकता है। आज के दौर में गरीब लोगों के मेधावी बच्चे डॉक्टर बनने के बारे में सोच भी नहीं सकते। भारत में अच्छे डॉक्टर गरीबी की पृष्ठभूमि से आए हैं। बेहतर आर्थिक पृष्ठभूमि वाले मेडिकल छात्र चिकित्सा व्यावसाय को पैसा कमाने वाले कोर्स समझते हैं। वह विशेष पाठयक्रमों में एडमिशन लेते हैं जिनमें ज्यादा पैसा है। प्रश्न यह है कि मेडिकल स्पेशलिस्ट बनने के लिए 3 से 5 करोड़ रुपए खर्च करने की आवश्यकता क्या है। दुनिया के अनेक देशों में मेडिकल एजुकेशन बिल्कुल मुफ्त है लेकिन भारत में यह बहुत महंगी है। यही कारण है कि भारत में प्रशिक्षित डॉक्टरों का भारी अभाव है।

भारत में होती हैं सबसे ज्यादा मौतें

भारत में जच्चा-बच्चा मृत्यु दर अन्य गरीब देशों के मुकाबले ज्यादा है। हर 12 मिनट में एक मां बच्चे को जन्म देते समय भारत में मर जाती है। प्रतिवर्ष 3 लाख बच्चे जन्म के चंद घंटों में दम तोड़ देते हैं। 12 लाख बच्चे अपना पहला जन्म दिवस भी नहीं बना पाते। भारत में 15 से 16ज्ञ महिलाओं को सिजेरियन की जरूरत पड़ती है। इसका अर्थ है कि देश में प्रतिवर्ष 52 लाख महिलाओं की आपरेशन से डिलिवरी जरूरी है। इसके लिए हमें दो 2 लाख महिला चिकित्सा विशेषज्ञों की जरूरत है। लेकिन देश में मात्र 50 हजार महिला चिकत्सक (गाइनेकोलॉजिस्ट) हैं। उनमें से आधे आपात स्थिति में काम नहीं करते, क्योंकि वह रात में डियुटी नहीं करना चाहते। विशेष बात यह है कि अधिकांश महिला चिकित्सक शहरों में रहती हैं। जबकि 60ज्ञ बच्चे ग्रामीण क्षेत्रों में पैदा होते हैं। हमें दो लाख एनएसथेटिस्ट चिकित्सकों की जरूरत है, लेकिन देश में 50 हजार से भी कम उपलब्ध हैं। देश को दो लाख शिशु रोग विशेषज्ञों की आवश्यकता है, लेकिन देश में मात्र 50 हजार शिशु रोग विशेषज्ञ हैं। देश में डेढ़ लाख रेडियोलॉजिस्ट की आवश्यकता है जबकि देश में कुल 10500 रेडियोलॉजिस्ट हैं। ऐसी स्थिति में जच्चा बच्चा की मृत्यु दर कैसे कम की जा सकती है।

मेडिकल कॉलेज खोलना आसान हो

वर्तमान स्थिति में देश में मेडिकल शिक्षा के लिए बजट बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। सरकार और एनएमसी को मेडिकल कॉलेज खोलने की संरचना एवं शर्तों में ढील देने की आवश्यकता है। भारी भरकम अधोसंरचना से लेकर तमाम तरह की शर्तें नियम-कानून मेडिकल शिक्षा की दिशा में सबसे बड़ी बाधा और भ्रष्टाचार का कारण बने हुए है। इन बाधाओं एवं भष्ट्राचार को खत्म करने की तुरंत आवश्यकता है। अनावश्यक फैकल्टी की संख्या बढ़ाने बड़ी-बड़ी इमारतों और अन्य सुविधाओं की जगह सीट की संख्या बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए 300 बिस्तर का अस्पताल चाहिए। तमाम तरह के डिपार्टमेंट चाहिए। डिपार्टमेंट के लिए विशेषज्ञ चाहिए। जो भारत में उपलब्ध नहीं है। यह सब आसानी से संभव नहीं हो पाता। इसी कारण भारत मेडिकल शिक्षा में पिछड़ रहा है। विदेश जाने वाले छात्रों की संख्या लगातार बढ़ रही है। विदेश में पढ़ने वाले छात्र भारतीय धन को विदेशों में खर्च करते है। छोटे-छोटे देशों से मेडीकल चिकित्सा लेने के बाद अमेरिका और यूरोप के देश उन्हें मान्यता देते है। भारत में उन्हें आसानी से स्वीकार नहीं किया जाता है। भारत में मेडीकल छात्रों के लिए सीटे बढ़ाने, अधोसंरचना में सुधार करने, एमबीबीएस, एमएस, एमडी एवं अन्य विशेषज्ञ तैयार करने के लिए पाठयक्रम एवं व्यवहारिक ज्ञान में बदलाव नहीं करेगा। स्थिति और बिगड़ती जायेगी। सरकार को मेडिकल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पाठ्यक्रम एवं संरचना में बदलाव के लिए आवश्यक सुधार करने, इंसपेक्टर राज और नियमों के मकड़जाल को खत्म करने की आवश्यकता है। कोरोना काल की महामारी के बाद तत्काल सरकार को इस संबंध में बदलाव करना चाहिए। (लेखक/ईएमएस-सनत कुमार जैन)

गणेश शंकर विद्यार्थी की लेखनी से कांपती थी अंग्रेज सरकार

(बलिदान दिवस (25 मार्च) पर विशेष)

गणेश शंकर विद्यार्थी पत्रकारिता जगत के ऐसे महान् पुरोधा थे, जिनकी लेखनी से ब्रिटिश सरकार इस कदर भयभीत रहती थी कि क्रांतिकारी लेखन के लिए उन्हें अंग्रेज सरकार द्वारा पांच बार सश्रम कारावास और अर्थदंड की सजा दी गई। उनके लेखों में ऐसी गजब की ताकत थी कि उनकी पत्रकारिता ने ब्रिटिश शासन की नींद हराम कर दी थी। जब उनकी कलम चलती थी तो ब्रिटिश हुकूमत की जड़ें हिल जाती थी। बेमिसाल क्रांतिकारी पत्रकारिता के कारण ही गणेश शंकर विद्यार्थी और उनका अखबार 'प्रताप' आज के दौर में भी पत्रकारिता जगत के लिए आदर्श माने जाते हैं। वह एक निर्भीक पत्रकार, समाजसेवी, महान क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी थे। वे स्वयं तो एक उच्च कोटि के पत्रकार थे ही, उन्होंने अनेक युवाओं को लेखक, पत्रकार तथा कवि बनने की प्रेरणा और ट्रेनिंग दी। कांग्रेस के विभिन्न आन्दोलनों में भाग लेने तथा ब्रिटिश सत्ता के अत्याचारों के विरूद्ध 'प्रताप' में निर्भीक लेख लिखने के कारण वे पांच बार जेल गए। जब भी उन्हें अंग्रेज सरकार द्वारा गिरफ्तार किया जाता तो उनकी अनुपस्थिति में 'प्रताप' का सम्पादन माखनलाल चतुर्वेदी तथा बालकृष्ण शर्मा 'नवीन' सरीखे साहित्य के दिग्गज संभाला करते थे।

26 अक्तूबर 1890 को उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के अतरसुइया मोहल्ले में एक स्कूल हैडमास्टर जयनारायण के घर जन्मे विद्यार्थी जी की प्रारम्भिक शिक्षा उर्दू तथा अंग्रेजी में हुई। इलाहाबाद में शिक्षण के दौरान ही उनका झुकाव पत्रकारिता की ओर हुआ। हिन्दी साप्ताहिक 'कर्मयोगी' के सम्पादन में वे पंडित सुन्दर लाल की सहायता करने लगे। कानपुर में अध्यापन के दौरान उन्होंने कर्मयोगी सहित कई और अखबारों में लेख लिखे और पत्रकारिता के जरिये स्वाधीनता आन्दोलन से गहरे जुड़ गए। कुछ समय बाद उन्होंने पत्रकारिता, सामाजिक कार्यों तथा स्वाधीनता आन्दोलन से जुड़ाव के चलते 'विद्यार्थी' उपनाम अपना लिया और गणेश शंकर से 'गणेश शंकर विद्यार्थी' हो गए। उनकी उत्कृष्ट लेखनशैली से प्रभावित होकर हिन्दी पत्रकारिता जगत के पुरोधा पं. महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 1911 में अपनी साहित्यिक पत्रिका 'सरस्वती' में उपसम्पादक के पद पर कार्य करने का ऑफर दिया किन्तु विद्यार्थी जी को ज्वलंत समाचारों, समसामयिक तथा राजनीतिक विषयों में ज्यादा दिलचस्पी थी, इसलिए उन्होंने द्विवेदी जी का प्रस्ताव स्वीकारने के बजाय महामना पं. मदन मोहन मालवीय के हिन्दी साप्ताहिक 'अभ्युदय' में नौकरी ज्वाइन की।

9 नवम्बर 1913 को उन्होंने एक क्रांतिकारी पत्रकार के रूप में कानपुर से स्वयं 'प्रताप' नामक पत्रिका निकालना शुरू कर दिया। प्रताप के जरिये विद्यार्थी जी किसानों, मजदूरों और ब्रिटिश अत्याचारों से कराहते गरीबों का दुख-दर्द उजागर करने लगे। ब्रिटिश शासनकाल की उत्पीड़न और अन्याय की क्रूर व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाना उनकी पत्रकारिता का सबसे महत्वपूर्ण अंग था, जो ब्रिटिश हुकूमत को फूटी आंख न सुहाया और इसीलिए अपनी इसी क्रांतिकारी पत्रकारिता का खामियाजा उन्हें कई मुकद्दमों, भारी जुर्माने और कई बार जेल जाने के रूप में भुगतना पड़ा। 1920 में उन्होंने 'प्रताप' का दैनिक संस्करण निकालना शुरू कर दिया, जो मूलतः किसानों, मजदूरों और पीडितों का हिमायती समाचारपत्र बना रहा। उन्होंने 'प्रताप' के अलावा 'प्रभा' नामक एक साहित्यिक पत्रिका तथा एक राजनीतिक मासिक पत्रिका का भी प्रकाशन किया।

घटना जनवरी 1921 की है, जब रायबरेली के एक ताल्लुकदार सरदार वीरपाल सिंह ने किसानों पर गोलियां चलावाई थी। 'प्रताप' के संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी ने उस घटनाक्रम का पूरा विवरण अपने अखबार में छापा, जिसके लिए उन्हें तथा 'प्रताप' छापने वाले शिवनारायण मिश्र पर मानहानि का मुकद्दमा दर्ज किया गया और उन्हें जेल हो गई। 16 अक्तूबर 1921 को विद्यार्थी जी ने स्वयं गिरफ्तारी दी और 22 मई 1922 को जेल से रिहा हुए। जेल में रहते हुए उन्होंने एक डायरी लिखी और रिहाई के बाद उन्होंने उसी पर आधारित 'जेल जीवन की झलक' नामक एक ऐसी श्रृंखला छापी, जिसे अत्यधिक पसंद किया गया और 'प्रताप' के साथ पाठकों का काफिला जुड़ता गया। उसके बाद तो अंग्रेजों ने उन्हें वक्त-बेवक्त लपेटने का कोई अवसर नहीं छोड़ा लेकिन विद्यार्थी अपने क्रांतिकारी विचारों से जरा भी नहीं डिगे।

जेल से रिहाई के कुछ ही समय बाद भड़काऊ भाषण देने के आरोप में उन्हें ब्रिटिश सरकार द्वारा फिर गिरफ्तार कर लिया गया और 1924 में तब रिहा किया गया, जब उनका स्वास्थ्य बहुत खराब हो गया था। 1925 में राज्यसभा विधानसभा चुनाव में वे कानपुर से चुने गए और कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन की स्वागत-समिति के प्रधानमंत्री भी नियुक्त हुए लेकिन 1929 में उन्होंने पार्टी की मांग पर त्यागपत्र दे दिया, जिसके बाद वे 1930 में उत्तर प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष चुन लिए गए और उन्हें प्रदेशभर में सत्याग्रह आन्दोलन का नेतृत्व करने की अहम जिम्मेदारी दी गई। उसी दौरान उन्हें फिर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया और गांधी-इरविन पैक्ट के बाद 9 मार्च 1931 को उनकी जेल से रिहाई हुई।

स्वाधीनता संग्राम के उस दौर में हिन्दू-मुस्लिम एक-दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग कर रहे थे लेकिन ब्रिटिश हुकूमत ने दोनों समुदायों की भावनाओं को भड़काने का ऐसा खेल खेला कि जगह-जगह हिन्दू-मुस्लिम साम्प्रदायिक दंगे भड़कने लगे और देशभर में साम्प्रदायिक हिंसा फैलने लगी। कानपुर शहर भी साम्प्रदायिक दंगों की आग में झुलस उठा। गणेश शंकर विद्यार्थी का मन इन दंगों से बड़ा व्यथित हुआ और वे स्वयं इन दंगों को रोकने तथा दोनों समुदायों में भाईचारा कायम करने के लिए लोगों को समझाते हुए घूमने लगे। कई जगहों पर वे लोगों को समझाने में सफल भी रहे और इन दंगों के दौरान उन्होंने हजारों लोगों की जान बचाई भी लेकिन वे स्वयं दंगाइयों की एक ऐसी टुकड़ी में फंस गए. जो उन्हें पहचानते नहीं थे। उसके बाद उनकी बहुत खोज की गई किन्तु वे कहीं नहीं मिले। आखिर में उनका पार्थिव शरीर एक अस्पताल में लाशों के ढ़ेर में पड़ा मिला, जो इतना फूल गया था कि लोग उसे पहचान भी नहीं पा रहे थे। हजारों लोगों की जान बचाने के बावजूद गणेश शंकर विद्यार्थी स्वयं धार्मिक उन्माद की भेंट चढ़ गए और इस प्रकार 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरू और सुखदेव को फांसी दिए जाने के दो ही दिन बाद देश ने 25 मार्च 1931 को अपनी कलम की ताकत से ब्रिटिश हुकूमत की रातों की नींद और दिन का चैन उड़ाने वाला निर्भीक, निष्पक्ष, ईमानदार, यशस्वी व क्रांतिकारी पत्रकार भी खो दिया। 29 मार्च 1931 को उनका अंतिम संस्कार किया गया।

गणेश शंकर विद्यार्थी जीवन पर्यन्त जिस धार्मिक कट्टरता तथा उन्माद के खिलाफ आवाज उठाते रहे, वही धार्मिक उन्माद उनकी जिंदगी लील गया। 27 अक्तूबर 1924 को विद्यार्थी जी ने 'प्रताप' में 'धर्म की आड़' शीर्षक से लेख में लिखा था, ''देश में धर्म की धूम है और इसके नाम पर उत्पात किए जा रहे हैं। लोग धर्म का मर्म जाने बिना ही इसके नाम पर जान लेने या देने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसे लोग कुछ भी समझते-बूझते नहीं हैं। दूसरे लोग इन्हें जिधर जोत देते हैं, ये लोग उधर ही जुत जाते हैं।'' वह गणेश शंकर विद्यार्थी ही थे, जिन्होंने श्याम लाल गुप्त पार्षद लिखित गीत 'झंडा ऊंचा रहे हमारा' को जलियांवाला हत्याकांड की बरसी पर 13 अप्रैल 1924 से गाया जाना शुरू करवाया था। ऐसे क्रांतिकारी पत्रकार और महान् स्वाधीनता सेनानी को उनके बलिदान दिवस पर शत-शत नमन।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं) (लेखक - योगेश कुमार गोयल/ईएमएस)

आज का इतिहास-25 मार्च

1507 फ्रांस नरेश लुई 12वें ने जेनोआ (इटली)पर हमला किया.
1815 नेपोलियन बोनापार्ट के खिलाफ आस्ट्रिया,ब्रिटेन,प्रसिया,रूस ने गठबंधन किया.
1983 सागर अनुसंधान के लिए अति आधुनिक जहाज सागरकन्या का जलावतरण किया गया था.
1941 द्वितीय विश्व युद्ध में रोम, बर्लिन, टोकियो गठबंधन में यूगोस्लाविया भी शामिल हो गया.
1957 इटली,बेल्जियम,पश्चिम जर्मनी, लक्जमबर्ग और नीदरलैंड ने साझा बाजार और यूराटोम के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किये.
1969 पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने ग्यारह वर्ष बाद सत्ता सेना को सौफ दी .
1975 सऊदी अरब के शाह फैजल की हत्या उनके भतीजे ने की.
1987 अफगानी विमानों की बमबारी में पाकिस्तानी सीमा पर 80अफगान छापामार और नागरिक मारे गए.
1820 ब्रिटिश उपन्यासकार ऐन ब्रोंट का जन्म.
1992 पाकिस्तान विश्वकप क्रिकेट चेम्पियन बना.
1988 बंगाल व उड़ीसा मे भयंकर तुफान से 200 मरे.
1911 न्यूयार्क सिटी,अमेरिका में ट्रेंगल शर्टवेस्ट फैक्ट्री मे आग लगने से145 लोगों की मृत्यु.
2000 सुरक्षा बलों ने पांच विदेशी आतंकवादियों को मार गिराया.
2004 गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर का नोहल मेडल चोरी हुआ.

शब्द पहेली - 7235

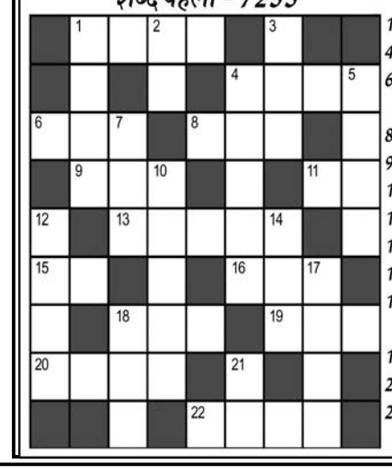

बाएँ से दाएँ

1.खटपट,ठनाठनी-4
4.पंजाब की एक नदी-4
6.चित्रकमेल,लम्बी गर्दनवाला पशु-3
8.दंड,दम,शामन-3
9.धरा,भूमि-3
11.शासन व्यवस्था,रहस्य-2
13.नवचंद्राकार-5
15.अकेला-2
16.दया,करुणा-3
18.बंदर का खेल दिखाने वाला-3
19.देवर्षि,देवमुनि-3
20.सब्जी,भाजी-4
22.कुंए पर पानी भरने का चबूतरा-4

ऊपर से नीचे

1.गुनाह,दोष,जुर्म-3
2.अपराधमुक्त,निवृत्त-2
3.सौत,दूसरी स्त्री-3
4.होशियार,गुणवान-5
5.भूकम्प-4
7.भेद,तुलना-3
10.परिचर्या-5
12.स्वभाव-4
14.स्थित होना-3
17.श्मशान-4
18.गृह,भवन-3
21.जीवन,जीव,स्फूर्ति-2

**शब्द पहेली -7234

यूएन में नहीं पारित हो सका रूसी प्रस्ताव

-मतदान में 13 सदस्य देशों ने नहीं लिया हिस्सा

जिनेवा(ईएनएस)। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वह रूसी प्रस्ताव पारित नहीं हो सका, जिसमें यूक्रेन की बढ़ती मानवीय जरूरतों को तो स्वीकार किया गया था, लेकिन रूसी आक्रमण का कोई उल्लेख नहीं था। रूस को प्रस्ताव पारित कराने के लिए 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद में न्यूनतम नौ वोट की आवश्यकता थी, साथ ही जरूरी था कि चार अन्य स्थायी सदस्यों अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन में से कोई भी वीटो का इस्तेमाल ना करे। हालांकि, रूस को केवल अपने सहयोगी चीन का समर्थन मिला, जबकि भारत सहित 13 अन्य परिषद सदस्यों ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया। इसे रूस की एक बड़ी विफलता के रूप में देखा जा रहा है। इस बीच, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने यूक्रेन और दो दर्जन अन्य देशों द्वारा तैयार किए गए एक प्रस्ताव पर विचार करना शुरू किया। करीब 100 देशों द्वारा सह-प्रायोजित किए गए प्रस्ताव में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि बढ़ती मानवीय आपात स्थिति के लिए रूस की आक्रामकता जिम्मेदार है।

संयुक्त राष्ट्र में रूस के राजदूत, वसीली नेबेंजिया ने वोट से पहले सुरक्षा परिषद को बताया था कि उसका प्रस्ताव ''राजनीतिक नहीं है'', बल्कि सुरक्षा परिषद के अन्य मानवीय प्रस्तावों की तरह है। उन्होंने स्पष्ट रूप से उस अमेरिकी दावे को खारिज किया कि रूस को इस तरह का प्रस्ताव पेश करने का कोई अधिकार नहीं था। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत लिंडा थॉमस ने कहा कि रूस ''अपने क्रूर कृत्यों को छुपाने के लिए इस परिषद का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है।'' वहीं, चीन के राजदूत झांग जून ने रूसी प्रस्ताव के पक्ष में अपने देश के वोट पर सफाई देते हुए कहा कि परिषद के सदस्यों को मानवीय मुद्दों पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए, तथा ''राजनीतिक मतभेदों को दूर करना'' एवं आम सहमति तक पहुंचने का प्रयास करना चाहिए। साथ ही, मानवीय संकट से निपटने के लिए सकारात्मक एवं व्यावहारिक प्रयास करने चाहिए। फ्रांस के राजदूत निकोलस डी रिवेरे ने प्रस्ताव को ''यूक्रेन के खिलाफ अपनी आक्रामकता को सही ठहराने के रूस के तरीकों में से एक बताया।'' मैक्सिको के राजदूत जुआन रेमन डी ला फुएंते ने कहा कि रूसी प्रस्ताव में ''जमीनी वास्तविकता'' से जुड़ा या ''मानवीय जरूरतों'' से संबंधित कुछ नहीं है।

उ कोरिया ने अपने पूर्वी तट से जापान के पास दागी मिसाइल

-मिसाइल उत्तरी जापान के सिर्फ 170 किमी पास दागी गई है

सियोल(ईएमएस)। उत्तर कोरिया ने गुरुवार को अपने पूर्वी तट से समुद्र की ओर एक अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल को दागा है। जापान के मंत्री मंत्री माकोतो ओनिकी का कहना है कि उत्तर कोरियाई बैलिस्टिक मिसाइल जापान के विशेष आर्थिक क्षेत्र में गिरी है। जानकारी के अनुसार इस बार बैलिस्टिक मिसाइल ने 6,000 किमी से अधिक की ऊंचाई पर उड़ान भरी है और यह अब तक का बड़ा रिकार्ड माना जाता है। दक्षिण कोरिया और जापान की सेनाओं के अनुसार यह 2017 के बाद की सबसे बड़ी मिसाइल है और उत्तरी जापान के सिर्फ 170 किमी पास दागी गई है।

दक्षिण कोरिया के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने कहा कि उसने उत्तर कोरिया से एक अज्ञात मिसाइल के प्रक्षेपण का पता लगाया है। जानकारी के अनुसार उत्तर कोरिया ने 2017 के बाद से ऐसी मिसाइलों की पूरी रेंज या क्षमता पर परीक्षण नहीं किया है। तानाशाह किम जोंग के नेतृत्व में उत्तर कोरिया ने इस साल अब तक 10 से ज्यादा मिसाइलों की टेस्टिंग की है। इसमें से एक मिसाइल का परीक्षण विफल रहा है। गौरतलब है कि उत्तर कोरिया के इन ताबड़तोड़ टेस्ट से दक्षिण कोरिया और अमेरिका खासे नाखुश हैं। अमेरिका ने इसके चलते कई प्रतिबंध भी लगा दिए हैं।

भारतीय विदेश सचिव श्रंगला और यूएन प्रमुख गुतारेस ने यूक्रेन, अफगानिस्तान के मसले पर की बातचीत

जिनेवा (ईएमएस)। भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रंगला ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुतारेस से यहां मुलाकात की और यूक्रेन, अफगानिस्तान और म्यांमार की बदलती परिस्थितियों सहित विश्व निकाय की सुरक्षा परिषद के एजेंडे पर विचार विमर्श किया। श्रंगला मंगलवार को न्यूयॉर्क पहुंचे और संयुक्त राष्ट्र तथा अरब देशों के लीग के बीच सहयोग को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) की ब्रीफिंग में बुधवार को हिस्सा लिया। यह ब्रीफिंग संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) की काउंसिल प्रेसिडेंसी के तहत आयोजित की गई। संरा सुरक्षा परिषद की ब्रीफिंग की अध्यक्षता यूएई के मंत्री खलीफा शाहीन अलमरार ने की। यूएनएससी की ब्रीफिंग के बाद श्रंगला ने संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में गुतारेस से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने ट्वीट किया, 'विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रंगला ने संरा महासचिव एंतोनियो गुतारेस से मुलाकात की।(तथा) यूक्रेन, अफगानिस्तान और म्यांमा सहित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एजेंडे पर विचार विमर्श किया।

सूत्रों ने बताया कि दोनों नेताओं के बीच बैठक करीब एक घंटे तक चली और उन्होंने यूक्रेन की स्थिति पर भी चर्चा की। ऐसा समझा जाता है कि गुतारेस ने कहा कि भारत उन कुछेक देशों में शामिल है जिनका पूरी दुनिया में सम्मान होता है और भारत जैसे देश को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है, क्योंकि मौजूदा स्थिति में यह दोनों पक्षों से सम्पर्क कर सकता है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से कई बार बातचीत की है और हिंसा के बजाय कूटनीतिक बातचीत और संवाद का रास्ता अपनाने की अपील की है। पिछले सप्ताह गुतारेस ने कहा था कि वह चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इजरायल और तुर्की सहित तमाम देशों से संपर्क बनाए हुए हैं, ताकि इस युद्ध की समाप्ति के लिए मध्यस्थता के प्रयास किये जा सकें।

सूत्रों ने बताया कि संरा महासचिव ने रूस-यूक्रेन युद्ध की वजह से पेट्रोलियम उत्पाद तथा खाद्य सामग्रियों पर पड़ने वाले प्रभावों पर भी चिंता जताई है, क्योंकि यदि यह संकट जारी रहता है तो कई देशों को गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। सूत्रों के अनुसार, गुतारेस संयुक्त राष्ट्र में भारत की भूमिका तथा इस बात को लेकर सकारात्मक थे, कि भारत के साथ बातचीत संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए महत्वपूर्ण होगी। श्रंगला के यूएनएससी की ब्रीफिंग में शामिल होने के कुछ घंटे बाद, 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद में, रूस के उस प्रस्ताव पर मतदान हुआ जिसमें यूक्रेन की बढ़ती मानवीय जरूरतों को तो स्वीकार किया गया था, लेकिन रूसी आक्रमण का कोई उल्लेख नहीं था। बहरहाल, वह प्रस्ताव पारित नहीं हो सका। रूस को प्रस्ताव पारित कराने के लिए 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद में न्यूनतम नौ वोट की आवश्यकता थी, साथ ही जरूरी था कि चार अन्य स्थायी सदस्यों अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन में से कोई भी 'वीटो' का इस्तेमाल ना करे। हालांकि, रूस को केवल अपने सहयोगी चीन का समर्थन मिला, जबकि भारत सहित 13 अन्य परिषद सदस्यों ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया।

पहले अश्वेत अफ्रीकी फ्रांसिस केरे को मिला आर्किटेक्चर क्षेत्र का सर्वोच्च अवॉर्ड

लंदन (ईएमएस)। आर्किटेक्चर के क्षेत्र के सबसे प्रतिष्ठित विश्वस्तरीय में सर्वोच्च अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्रित्जकर आर्किटेक्चर अवार्ड इस बार डियेबेडो फ्रांसिस केरे को मिल रहा है। इस सम्मान को हासिल करने वाले वह पहले अश्वेत अफ्रीकी हैं। बुर्किना फासो, पश्चिमी अफ्रीका में जन्मे केरे ने वास्तुकला के अभ्यास के लिए एक डिजाइनिंग स्कूल तैयार किया और एक मेडिकल सुविधा का निर्माण भी किया। इसकी खास बात यह है कि इसे स्थानीय समुदायों की मदद से बहुत कम संसाधनों की मदद से बनाया गया। इसके निर्माण के लिए किफायती और टिकाऊ सामग्री का सावधानी से चुनाव किया गया। उनके इसी कदम ने उनकी आर्किटेक्चर फर्म को वैश्विक पहचान दिलाई। 56 साल के फ्रांसिस केरे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त आर्किटेक्ट हैं। पढाई के लिए उन्हें बचपन में अपने परिवार को छोड़ कर पास के शहर में जाना पड़ा था। वह शुरू से इस बात को लेकर आश्वस्त रहे कि उनके देश में केवल शिक्षा ही है जो उन्हें बेहतर बना सकती है। इसी सोच के साथ केरे कारपेंटरी में छात्रवृत्ति हासिल करके बर्लिन चले गए और फिर वहां पर वास्तुकला की पढ़ाई पूरी की। अपनी पढ़ाई के दौरान ही इन्होंने एक प्राथमिक स्कूल का डिजाइन तैयार कर लिया था। जर्मनी में उन्होंने स्कूल निर्माण के लिए धन जुटाने के लिए एक फाउंडेशन का निर्माण किया जिसका पहले नाम था, गांडो के लिए ईंड, जिसका नाम बदलकर केरे फाउंडेशन रखा गया।

यह स्कूल टिकाउ इमारतों के निर्माण के मामले में आदर्श माना जाता है। जहां इमारत को ठंडा रखने के लिए हवादार बनाया गया है और इसके निर्माण में स्थानीय संसाधनों का व्यापक स्तर पर इस्तेमाल किया गया है। स्थानीय संसाधन से मतलब सामग्री और श्रम दोनों ही स्थानीय स्तर पर इस्तेमाल होता है। इस तर्ज पर इन्होंने पहला स्कूल 2001 में बनाया था। इसकी सफलता को देखते हुए उन्होंनें आगे कुछ और परियोजनाएं तैयार की, एक लाइब्रेरी बनाई। उनके इस प्रक्रिया को देखकर पड़ौस के गांव भी प्रोत्साहित हुए और सामुदायिक स्तर पर काम करके उन्होंनें भी अपने गांवों में स्कूलों को निर्माण किया। उनके काम की सफलता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पहले स्कूल के निर्माण से 15 साल बाद उन्हें बुरकिना फासो की राष्ट्रीय संसद से न्यौता मिला, इसके बाद फ्रांसिस ने देश की सीमा को लांघते हुए अफ्रीका के बेनिन, केन्या, माली, मोजांबिक में भी काम किया। विश्व स्तर पर वह यूरोप, अमेरिका, और एशिया में भी प्रोजेक्ट कर चुके हैं।

यह आर्किटेक्चर की दुनिया का सर्वोच्च सम्मान है। हर साल यह किसी एक आर्किटेक्ट को उसके श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है। इस साल यानी 45 वां सम्मान पहली बार किसी अश्वेत अफ्रीकी को हासिल हुआ। केरे के लिए यह सम्मान इसलिए भी मायने रखता है क्योंकि उन्होंनें अपनी कला के जरिए स्थानीय स्तर की भूमिका को अहमियत दी है। इसके अलावा उनकी डिजाइन में पर्यावरण और किफायत का बहुत ध्यान रखा जाता है।

बांग्लादेश के एक स्कूल ने भी लगाई बुर्के पर लगाई पाबंदी

-हिजाब में घुस जाते थे लड़के, हंगामा

ढाका (ईएमएस)। भारत राज्य कर्नाटक की ही तरह बांग्लादेश के नोआखाली के सेनबाग उपजिले में एक स्कूल के क्लासरूम में छात्राओं के बुर्का पहनने पर पाबंदी लगा दी गई है। स्कूल के इस आदेश के बाद जगह-जगह पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक, स्कूल की तरफ एक नोटिस में कहा गया था कि लड़कियां कक्षा में दाखिल होने के बाद अपना चेहरा नहीं ढक सकती हैं। हालांकि, बाद में मैनेजमेंट ने इस नोटिस को वापस ले लिया। इस पूपे घटनाक्रम के दो सप्तास से अधिक समय हो गए हैं। इसके बावजूद लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हाथों में पोस्टर-बैनर लिए लोग इसकी आलोचना कर रहे हैं। बीबीसी ने अपनी रिपोर्ट में स्थानीय लोगों के हवाले से कहा है कि स्कूल प्रबंधन कमेटी के चुनाव के कारण से इस मामले को उछाला गया है। हालांकि, स्कूल प्रशासन का कहना है कि नोटिस की गलत व्याख्या की गई है। भ्रम की स्थिति के कारण नोटिस वापस लेना पड़ा।

मालूम हो कि स्कूल के बाहर मानव श्रंखला बनाकर विरोध प्रदर्शन कर अपने गुस्से का इजहार किया। वहीं, एक स्थानीय पुलिस अधिकारी ने कहा कि लड़कियों की क्लास में लड़कों के बुर्का पहनकर आने की कई घटना सामने आई थी। लड़कियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए स्कूल प्रशासन ने इस तरह का फैसला लिया। स्कूल प्रबंधन ने कक्षा में प्रवेश करने के बाद चेहरा नहीं ढकने का एक निर्देश जारी किया। उन्होंने कहा कि नोटिस में बुर्का ना पहनने या उसपर पाबंदी की कोई बात नहीं थी। उन्होंने कहा कि कई बार स्कूल में नहीं पढ़ने वाली लड़कियां भी क्लास में आ जाती थी।

बीबीसी ने अपनी रिपोर्ट में स्कूल प्रबंधन के हवाले से कहा है कि स्कूल के पास एक बाजार में लड़कों ने एक अड्डा बना लिया था। बाजार समिति ने इसके खिलाफ कार्रवाई की। इसके बाद वे लड़के स्कूल को अपना अड्डा बना लिया। लड़कियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हमने कक्षा के अंदर चेहरा नहीं ढकने का आदेश जारी किया। इस पूरे प्रकरण पर लेखिका तस्लीमा नसरीन ने कहा, ''नोआखली के शेर-ए-बांग्ला हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक मोजम्मेल हुसैन ने कक्षाओं में बुर्के पर प्रतिबंध लगा दिया। इसलिए बुर्का समर्थक लोगों ने प्रधानाध्यापक के फैसले का विरोध किया। हेडमास्टर ने कहा कि उन्होंने कक्षाओं में बुर्का पर प्रतिबंध लगा दिया क्योंकि अज्ञात पुरुष और बाहरी लोग कक्षाओं में प्रवेश करने के लिए बुर्का पहन सकते थे।''

यूक्रेन पर रायायनिक और परमाणु हमले की सूरत में क्या कदम उठाएगा अमेरिका

-राष्ट्रपति जो बाइडेन ले सकते हैं बड़ा फैसला

ब्रसेल्स (ईएमएस)। युद्धग्रस्त देश यूक्रेन के बिगड़ते हालात पर बात करने के लिए गुरुवार को अमेरिका के राष्ट्रपति नाटो और अपने सहयोगियों के साथ एक अहम बैठक करने वाले हैं। ये बैठक इसलिए भी बेहद खास है क्योंकि ब्रसेल्स में अपने चार दिवसीय दौरे पर आने से पहले ही अमेरिका ने रूस के करीब 14 अधिकारियों को स्वदेश वापस भेजने का आदेश दे दिया था। इसके अलावा आज होने वाली इस बैठक में रूस पर और अधिक प्रतिबंध लगाने का भी एलान किया जा सकता है।

इसके अलावा उनकी योजना पौलेंड की राजधानी वर्सा में होने वाली एक खास बैठक में शिरकत करने की भी है। यहां पर भी यूक्रेन और रूस के मसले पर ही बात होनी है। ये दोनों बैठक इसलिए भी हो रही हैं क्योंकि अमेरिका को इस बात की आशंका है कि रूस यूक्रेन पर साइबर, केमिकल और न्यूक्लियर अटैक तक कर सकता है। ऐसे में अमेरिका और उसके सहयोगी देश क्या कदम उठाएंगे, इस पर इस बैठक में चर्चा होगी।

इस बीच एएफपी ने बताया है कि फिनलैंड और स्वीडन के लोगों ने एक ओपेनियन पोल में ये माना है कि उन्हें नाटो का सदस्य बनना चाहिए। रूस और यूक्रेन की लड़ाई के बीच आ रहे ये पड़ाव काफी खास हैं। आपको बता दें कि रूस के यूक्रेन पर हमले की सबसे बड़ी वजह नाटो ही है। रूस नहीं चाहता है कि यूक्रेन नाटो का सदस्य बने। यदि ऐसा हुआ तो नाटो की फौज और उसके हथियार रूस की सीमा तक पहुंच जाएंगे, जो उसके लिए सही नहीं होगा।

आपको बता दें कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद से यूरोप अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। उसके ऊपर रूस के परमाणु और रसायनिक हमले की आशंका काफी अधिक है। बाइडन ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि ये एक असली डर है। रूस और यूकेन की लड़ाई से अब तक 35 लाख लोग शरणार्थी जीवन बिताने को मजबूर हो रहे हैं। यहां पर ये भी बताना जरूरी है कि अमेरिका, रूस और ब्रिटेन ने 1994 में यूक्रेन की सुरक्षा के लिए एक बुडापेस्ट मैमोरेंडम साइन किया था। लेकिन मौजूदा समय में जहां रूस के हमलों से यूक्रेन तबाह हो रहा है वहीं अमेरिका और ब्रिटेन रूस पर प्रतिबंध लगाने के अलावा कुछ कर नहीं पा रहे हैं।

राष्ट्रपति बाइडन ने इसको असली खतरा बताया है। बाइडन लगातार इस बात की आशंका जता रहे हैं कि रूस यूक्रेन पर केमिकल और परमाणु हमला कर सकता है। इस युद्ध की वजह से पौलेंड की सीमा पर हजारों की संख्या में रिफ्यूजी मौजूद हैं। युद्ध के चलते खाने-पीने के सामान की भी किल्लत हो रही है। आशंका यहां तक जताई जा रही है कि यदि जल्द ही हालात नहीं सुधरे तो भूखमरी के हालात भी पैदा हो सकते हैं। बाइडन आज होने वाली बैठक में इस बारे में भी चर्चा करेंगे कि रूस के राष्ट्रपति को युद्ध अपराधी घोषित किया जा सके।

शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद

मुंबई (ईएमएस)। मुम्बई शेयर बाजार गुरुवार को गिरावट के साथ बंद हुआ। बाजार में यह गिरावट बैंक और वित्तीय शेयरों में नुकसान से बिकवाली हावी होने के कारण आई है। बाजारों में दिन भर उतार-चढ़ाव जारी रहा पर अंत में यह गिरावट पर बंद हुआ। दिन भर के कारोबार के बाद तीस शेयरों पर आधारित बीएसई सेंसेक्स 90 अंक करीब 0.15 फीसदी की गिरावट के साथ ही 57,595.68 पर बंद हुआ। वहीं कारोबार के दौरान यह 57,138.51 के निम्न स्तर और 57,827.99 के शीर्ष स्तर तक पहुंचा।

इसी प्रकार पचास शेयरों वाला नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 23 अंक यानी 0.13 फीसदी की गिरावट के साथ ही 17,222.75 अंक पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से कोटक महिंद्रा बैंक, टाइटन, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी, महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति, इंडसइंड बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर लि., एक्सिस बैंक और भारतीय स्टेट बैंक के शेयर सबसे ज्यादा गिरे।

निफ्टी पर बैंक और फाइनेंशियल इंडेक्स में 1.5 फीसदी से ज्यादा की कमी दर्ज की गयी लेकिन मीडिया इंडेक्स 6 फीसदी बढ़ा। आटो इंडेक्स भी नुकसान के साथ ही लाल निशान पर बंद हुआ। वहीं फार्मा, एफएमसीजी, मेटल, आईटी और रियल्टी इंडेक्स लाभ के साथ ही हरे निशान पर बंद हुए हैं। सेंसेक्स के 30 में से 16 शेयर हरे निशान पर 12 लाल निशान पर बंद हुए हैं। डॉ. रेड्डीज लैबोरेटरीज, अल्ट्राटेक सीमेंट, रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा स्टील, टेक महिंद्रा, एनटीपीसी, आईटीसी, टीसीएस और एचसीएल टेक्नोलॉजीज के शेयर ऊपर आये हैं। जबकि कोटक बैंक, टाइटन, एचडीएफसी बैंक और एमएंडएम के शेयर गिरे हैं।

पाकिस्तान- लाहौर में क्रांतिकारी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव दी गई श्रद्धांजलि

लाहौर (ईएमएस)। अंग्रेजों से लोहा लेकर आजादी की लड़ाई लड़ने वाले क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को पाकिस्तान के लाहौर में बुधवार को नागरिक समाज ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। लोगों ने लाहौर के शादमान चौक पर तीनों शहीदों को पुष्जांपलि अर्पित की, जहां उन्हें 23 मार्च, 1931 को फांसी दी गई थी। इस दौरान मौजूद लोगों ने उस स्थान पर तीनों शहीदों को सलाम किया, जहां उन्हें फांसी दी गई थी। इस कार्यक्रम का आयोजन पाकिस्तान के भगत सिंह मेमोरियल फाउंडेशन द्वारा किया गया और कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा चाक-चौबंद रही क्योंकि धार्मिक चरमपंथियों की धमकी को ध्यान में रखते हुए लाहौर उच्च न्यायालय ने कड़ी सुरक्षा के निर्देश दिए थे। तीनों शहीदों को श्रद्धांजलि देने के बाद फाउंडेशन के अध्यक्ष इम्तियाज रशीद कुरैशी ने कहा कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के बलिदान को हमेशा याद रखा जाएगा।

रूस के परमाणु हमले का खौफ, फ्रांस ने तैनात की परमाणु बमों से लैस 3 पनडुब्बियां

पेरिस (ईएमएस)। यूक्रेन पर रूसी हमले के 30 दिन गुजर जाने के बाद भी जीत नहीं मिलने पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के परमाणु हमला करने का डर बढ़ता जा रहा है। रूसी सेना अपनी महाविनाशक हाइपरसोनिक मिसाइलों से लेकर कई जंगी घातक रॉकेट के जरिए यूक्रेन पर बमों की बारिश कर रही है लेकिन उसे कोई खास सफलता नहीं मिल रही है। इससे रूस के यूक्रेन की राजधानी कीव पर परमाणु हमला करने का डर सताने लगा है। इसी खतरे को देखते हुए अब नाटो सदस्य फ्रांस ने कई दशक बाद परमाणु बम से लैस अपनी 3 पनडुब्बियों को समुद्र में उतार दिया है। फ्रांसीसी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक करीब 30 साल बाद ऐसा पहली बार हो रहा है जब फ्रांस ने अपनी 3 पनडुब्बियों को एकसाथ समुद्र में गश्त के लिए उतारा है। इससे पहले रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी यूक्रेन युद्ध को देखते हुए अपनी परमाणु सेना को अलर्ट कर दिया था और नाटो देशों को चेतावनी दी थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि फ्रांस की टेरियोंफ्लांट क्लास की परमाणु मिसाइलों से लैस 4 में से 2 पनडुब्बियां अपने ठिकाने से निकल चुकी हैं जो अटलांटिक महासागर में स्थायी तौर पर गश्त लगाती रहती हैं।

परमाणु एक पनडुब्बी पहले से समुद्र में मौजूद है। करीब 30 साल पहले शीतयुद्ध के दौरान अंतिम बाद 3 पनडुब्बियों को एक साथ तैनात किया गया था। इस दौरान अमेरिका और सोवियत संघ के बीच मध्यम दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों को लेकर गतिरोध पैदा हो गया था। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि फ्रांस के राष्ट्रपति के सीधे कमांड में आने वाली इन पनडुब्बियों को खतरे को देखते हुए तैनात किया गया है। परमाणु ऊर्जा से चलने वाली ये सबमरीन दुनिया में कहीं भी जा सकती हैं और महीनों तक पानी के अंदर ही छिपी रहती हैं। फ्रांसीसी सबमरीन के अंदर 16 परमाणु बम से लैस मिसाइलों को ले जाने की क्षमता होती है। ये परमाणु बम 150 किलोटन का होता है। इसकी मारक क्षमता 6000 से लेकर 8000 किमी तक होती है। इस बीच फ्रांसीसी सेना ने हवा से दागे जाने वाली परमाणु मिसाइल का भी सफल परीक्षण करके अपने इरादे साफ कर दिए हैं।

नेपाल ने डिजिटल लेनदेन के लिए भारत के यूपीआई का इस्तेमाल शुरू किया

काठमांडू (ईएमएस)। नेपाल ने डिजिटल लेनदेन के लिए भारत द्वारा तैयार एकीकृत भुगतान इंटरफेस का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) द्वारा गुरुवार को ट्वीट किए लेख के मुताबिक, इस साल की शुरुआत में भूटान ने डिजिटल लेनदेन के लिए भीम-यूपीआई आधारित डिजिटल लेनदेन को अपनाया था।''

लेख में कहा गया है, कि कई देशों ने कोविन एप की भी प्रशंसा की है। इस एप को कोविड की शुरुआती अवधि के दौरान टीकाकरण के लिए विकसित किया गया था। अब नेपाल ने भी भारत की यूपीआई प्रणाली को अपनाया है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, भीम-यूपीआई लोगों के पसंदीदा भुगतान विकल्प के रूप में उभरा है। 28 फरवरी, 2022 तक इसके जरिये 8.27 लाख करोड़ रुपये के मूल्य के रिकॉर्ड 452.75 करोड़ डिजिटल भुगतान किए गए हैं।

देश में अगले दो दशकों में 2,000 विमानों की जरूरत : एयरबस

हैदराबाद (ईएमएस)। दिग्गज विमान विनिर्माता एयरबस का कहना है ?कि भारत में विमानन परिदृश्य बेहतर होने से यहां पर अगले दो दशकों में एयरबस के एयरलाइन विपणन प्रमुख (भारत एवं दक्षिण एशिया) बेंट मैकब्रैटनी ने कहा कि भारत में अगले दो दशकों में बड़ी संख्या में नए विमानों की जरूरत पैदा होगी। इनमें से 1,770 विमान छोटे आकार के होने चाहिए जबकि 440 विमान मध्यम एवं बड़े आकार वाले चाहिए। मैकब्रैटनी ने कहा कि भारतीय विमानन परिदृश्य के विस्तार की संभावनाओं को देखते हुए उसे वर्ष 2040 तक 34,000 अतिरिक्त पायलट और 45,000 तकनीकी स्टाफ की भी जरूरत होगी। उन्होंने कहा कि भारत में हवाई परिवहन के अगले दो दशकों में 6.2 प्रतिशत की दर से बढ़ने की संभावना है।

पेट्रोल और डीजल में तेजी से महंगाई और बढ़ने की संभावना

नई दिल्ली (ईएमएस)। रूस और यूक्रेन युद्ध के कारण क्रूड में तेजी के बीच पिछले दो दिनों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 1.60 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। एलपीजी के दाम भी बढ़े हैं। खुदरा ईंधन विक्रेता कंपनियों के अधिकारियों का कहना है कि आने वाले समय में पेट्रोल-डीजल और एलपीजी की कीमतों में और बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। कुल मिलाकर इससे महंगाई के और बढ़ने की संभावना है। पिछले साल नवंबर के बाद से ब्रेंट क्रूड की कीमतों में 40 फीसदी से ज्यादा की तेजी आई है। ईसीआरए लिमिटेड में कॉरपोरेट रेटिंग के एक व?रिष्ठ अ?धिकारी का कहना है ?कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें आगे अभी और बढ़नी हैं। ईंधन की बढ़ती कीमतों से भारतीय परिवारों पर दबाव बढ़ सकता है। इससे वस्तुओं और सेवाओं की मांग में कमी आ सकती है। तेज आर्थिक विकास के लिए ब्याज दरों को कम रखने की आरबीआई की प्रतिबद्धता पर भी महंगाई का दबाव पड़ेगा। पूरे साल के लिए ईंधन की कीमतों में 10 फीसदी की बढ़ोतरी से उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) आधारित महंगाई यानी खुदरा महंगाई 42 बेसिस प्वाइंट और थोक महंगाई 100 बेसिस प्वाइंट तक बढ़ जाती है। क्रूड में मौजूदा तेजी न सिर्फ अर्थव्यवस्था पर महंगाई का दबाव बढ़ाएगी बल्कि निजी खपत पर भी इसका प्रभाव दिखेगा।

सोना और चांदी की चमक बढ़ी

नई दिल्ली (ईएमएस)। एमसीएक्स पर सोने की कीमत गुरुवार को 0.20 फीसदी बढ़कर 51,869 रुपए प्रति दस ग्राम पर पहुंच गई है, वहीं चांदी के दाम में 0.10 फीसदी की तेजी आई है। इसके बाद चांदी का भाव उछलकर 68,330 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया है। यहां बता दें कि आभूषण बनाने के लिए ज्यादातर 22 कैरेट का ही इस्तेमाल होता है। गौरतलब है ?कि कुछ लोग 18 कैरेट सोने का भी इस्तेमाल करते हैं। आभूषण पर कैरेट के हिसाब से हॉल मार्क बना होता है। 24 कैरेट सोने के आभूषण पर 999 लिखा होता है, जबकि 23 कैरेट पर 958, 22 कैरेट पर 916, 21 कैरेट पर 875 और 18 कैरेट पर 750 लिखा होता है। देश भर में सोने के आभूषणों की कीमत उत्पाद शुल्क, राज्य करों और मेकिंग चार्ज के कारण बदलती रहती है।

यूक्रेन को जिन तीन देशों ने दिया था सुरक्षा का भरोसा, वही बने दुश्मन!

1994 में रूस के साथ ब्रिटेन और अमेरिका ने मिलकर बुडापेस्ट ज्ञापन पर ?किए थे हस्ताक्षर

कीव (ईएमएस)। रूस और यूक्रेन के युद्ध को एक माह पूरा हो गया है। इस एक माह के दौरान रूस ने यूक्रेन पर जबरदस्त हमला कर यूक्रेन को दशकों पीछे पहुंचा दिया है। इस लड़ाई में पहले रूस ने न तो हाईटेक मिसाइलों को इस्तेमाल किया था और न ही एयर स्ट्राइक की थी, लेकिन अब वो इस लड़ाई को जल्द खत्म करने और जीतने के लिए सभी चीजों का इस्तेमाल कर रहा है लेकिन इन सभी के बीच एक बात काफी दिलचस्प है। वो ये कि कभी रूस ने अन्य दो देशों के साथ मिलकर एक ज्ञापन पर हस्ताक्षर ?किए थे, जिसका मकसद यूक्रेन की जरूरत पड़ने पर हर संभव सुरक्षा करना था। इसको बुडापेस्ट ज्ञापन के नाम से जाना जाता है। हालांकि अब रूस ही उसकी बर्बादी का कारण बन गया है। गौरतलब है कि सोवियत संघ को ?विघटन के बाद दिसंबर 1991 में यूक्रेन एक आजाद राष्ट्र के तौर पर सामने आया था। 1994 में रूस के साथ ब्रिटेन और अमेरिका ने मिलकर बुडापेस्ट ज्ञापन साइन किया था। अब जहां रूस यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, वहीं अमेरिका और ब्रिटेन प्रतिबंध लगाने के अलावा कुछ नहीं कर पा रहे हैं। कुल मिलाकर इस समय यूक्रेन की बर्बादी की वजह ये तीनों ही बने हुए हैं। इसके बाद ही रूस ने यूक्रेन में स्थित अपने सभी परमाणु केंद्रों को भी निष्क्रय कर दिया था।

गौरतलब है ?कि यूक्रेन के नाटो की तरफ झुकाव का वजह से ही इस लड़ाई की शुरूआत हुई है। हालांकि यूक्रेन ने इसकी शुरूआत अप्रेल 2008 में की थी। आज तक भी उसको इसकी सदस्यता हासिल नहीं हो सकी है। अब यूक्रेन का भी धैर्य जवाब देने लगा है। यही वजह है कि नाटो को लेकर वो अब काफी आक्रामक दिखाई दे रहा है। ऐसा इसलिए, क्योंकि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की कह चुके हैं कि जब वो राष्ट्रपति बने थे तभी उन्होंने नाटो के गोलमोल रवैये की वजह से इस मुद्दे को ठंडे बस्ते में डाल दिया था। इतना ही नहीं जेलेंस्की यहां तक कह चुके हैं कि नाटो रूस से डरता है इसलिए वो उसको सदस्यता नहीं दे रहा है। पर ये भी बताना जरूरी है कि रूस हमेशा से ही नाटो के विस्तार को घोर विरोधी रहा है। रूस चाहता है कि नाटो जहां पहले था, वहीं तक उसको सीमित रहना चाहिए। नाटो के विस्तार को रूस अपने लिए बड़ा खतरा मानता है। यूक्रेन और रूस की लड़ाई में अमेरिका समेत अन्य देशों के शामिल न होने के पीछे रूस का ही दबाव है।

विज्ञान भी जूता घर के बाहर उतारने की करता है हिमायत

-नए रिसर्च में वैज्ञानिकों ने दी बड़ी सलाह

लंदन (ईएमएस)। पर्यावरण केमिस्ट ने एक दशक तक घर के अंदर के वातावरण और लोगों को अपने घरों में किन दूषित पदार्थों का सामना करना पड़ता है, इस बात की जांच की है। हालांकि, हमारे डस्टसेफ कार्यक्रम के माध्यम से, घर के अंदर के वातावरण की हमारी परीक्षा अभी पूरी नहीं हुई है, ल

लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती हैः राष्ट्रपति कोविंद

- भारत के राष्ट्रपति ने गांधीनगर में गुजरात विधानसभा के सदस्यों को संबोधित किया

अहमदाबाद (ईएमएस) भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज गुजरात विधानसभा के सदस्यों को संबोधित किया। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। राष्ट्रपति ने कहा कि विधानसभा के सदस्य अपने क्षेत्र और राज्य के लोगों के प्रतिनिधि होते हैं, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि लोग उन्हें अपने भाग्य का निर्माता मानते हैं। लोगों की उम्मीदें और आकांक्षाएँ उनसे जुड़ी हैं। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों के लिए लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने का प्रयास सर्वोपरि होना चाहिए। गांधीनगर में गुजरात विधानसभा पहुंचे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का मुख्यमंत्री भूपेंद्रभाई पटेल, विधानसभा अध्यक्ष नीमाबहेन आचार्य और राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति ने भारत के आज़ादी के अमृत महोत्सव मनाए जा रहे होने का उल्लेख करते हुए कहा कि स्वतंत्रता और उसके अमृत महोत्सव का जश्न मनाने के लिए गुजरात से बेहतर कोई जगह नहीं है। गुजरात राज्य के लोग स्वतंत्र भारत की कल्पना करने वाले लोगों में अग्रणी थे। 19वीं सदी के अंतिम दशकों में दादाभाई नौरोजी और फिरोज़शाह महेता जैसी हस्तियों ने भारतीयों के अधिकारों के लिए आवाज़ उठाई। स्वतंत्रता के उस संघर्ष को गुजरात के लोगों ने लगातार मज़बूत किया और अंततः महात्मा गांधी के मार्गदर्शन में वह संघर्ष भारत की स्वतंत्रता में परिणामित हुआ। राष्ट्रपति ने कहा कि महात्मा गांधी ने न केवल भारत के स्वतंत्रता संग्राम को नेतृत्व प्रदान किया, बल्कि पूरी दुनिया को एक नया रास्ता, एक नई सोच और एक नया दर्शन भी दिखाया। आज जब भी दुनिया में किसी भी तरह की हिंसा होती है, तब हमें बापू द्वारा दिए गए 'अहिंसा' के मंत्र के महत्व का एहसास होता है राष्ट्रपति ने कहा कि गुजरात का इतिहास अनूठा है। महात्मा गांधी और सरदार पटेल की इस भूमि को सत्याग्रह की भूमि कहा जा सकता है। पूरे विश्व में औपनिवेशवाद के ख़िलाफ़ सत्याग्रह के मंत्र को एक अमोघ शस्त्र के रूप में स्थापित किया गया था। बारडोली सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह और दांडी मार्च ने न केवल हमारे स्वतंत्रता संग्राम को एक नया रूप दिया, बल्कि विरोध की अभिव्यक्ति और जन आंदोलन के संचालन को भी एक नया आयाम दिया। राष्ट्रपति ने कहा कि सरदार पटेल ने स्वतंत्र भारत को उसका एकीकृत रूप दिया और प्रशासन की नींव को मज़बूत किया। नर्मदा के तट पर उनकी प्रतिमा 'द स्टैच्यू ऑफ़ यूनिटी', जो दुनिया की सबसे ऊँची प्रतिमा है, उनकी स्मृति में एक कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से एक छोटा सा उपहार है। भारत के लोगों के दिलों में उनका कद उससे भी ऊँचा है।

राष्ट्रपति ने कहा कि गुजरात ने राजनीति के अलावा सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में भी अहम भूमिका निभाई है। नरसिंह मेहता की इस भूमि पर अध्यात्म का बहुत प्रभाव रहा है। उनका भजन ठवैष्णवजन तो तेने कहिए, जे पीड पराई जाणे रेठ हमारे स्वतंत्रता संग्राम का गीत बन गया। इसने भारतीय संस्कृति के मानवतावाद का भी प्रसार किया था। राष्ट्रपति ने कहा कि गुजरात के लोगों की उदारता भारतीय संस्कृति की एक प्रमुख विशेषता है। इस क्षेत्र में प्राचीन काल से सभी संप्रदायों और समुदायों के लोग भाईचारे के साथ आगे बढ़ रहे हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि आधुनिक युग में गुजरात ने विज्ञान के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया है। जहाँ डॉ. होमी जहाँगीर भाभा को भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक माना जाता है, वहीं भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला के संस्थापक डॉ. विक्रम साराभाई को भारतीय विज्ञान और विशेष रूप से भारत के अंतरिक्ष अनुसंधान के अग्रणी के रूप में सम्मानित किया जाता है। राष्ट्रपति ने कहा कि 1960 में राज्य की स्थापना होने के बाद गुजरात उद्योग और नवाचार के माध्यम से विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि गुजरात की धरती पर शुरू हुई श्वेत क्रांति ने पोषण के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव किया है। आज दूध के कुल उत्पादन और खपत के मामले में भारत दुनिया में प्रथम स्थान पर है। गुजरात की दूध सहकारी समितियाँ इस सफलता की अग्रदूत रही हैं। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने गुजरात में सहकारी संस्कृति की सफलता के लाभों को पूरे देश में पहुँचाने के उद्देश्य से केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय का गठन किया है। राष्ट्रपति ने कहा कि गुजरात विधानसभा ने इस राज्य के समग्र विकास के लिए कई क्रांतिकारी क़दम उठाए हैं। गुजरात पंचायत विधेयक, 1961 और गुजरात अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा अधिनियम, 1961 द्वारा क्रमशः स्थानीय स्वशासन और शिक्षा के क्षेत्र में एक प्रगतिशील प्रणाली स्थापित की गई थी। गुजरात एकमात्र ऐसा राज्य है, जहाँ इनस्ट्रक्चर में निवेश और विकास को प्रोत्साहित करने के लिए विधानसभा द्वारा गुजरात इनस्ट्रक्चर डेवलपमेंट एक्ट, 1999 पारित किया गया था। भविष्योन्मुखी क़ानून बनाने की दिशा में इस विधानसभा द्वारा पारित गुजरात जैविक कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2017 भी उल्लेखनीय है। राष्ट्रपति ने गुजरात की बहुआयामी प्रगति में अपने योगदान के लिए गुजरात की वर्तमान और पिछली सरकारों के साथ-साथ गुजरात विधानसभा के वर्तमान और पूर्व सदस्यों की प्रशंसा की।

राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों से गुजरात के विकास मॉडल को एक अनुकरणीय उदाहरण के रूप में देखा जा रहा है, जिसे देश के किसी भी क्षेत्र और राज्य में लागू किया जा सकता है। साबरमती रिवरंट शहरी परिवर्तन का एक प्रभावशाली उदाहरण है। पर्यावरण को सुरक्षित रखते हुए साबरमती और इसके निवासियों के बीच संबंधों को एक नया आयाम दिया गया है। देश के नदी के किनारे बसे अन्य सभी शहरों के लिए यह एक अच्छा उदाहरण हो सकता है। राष्ट्रपति ने कहा कि जब हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तब यह हमारा कर्तव्य है कि हम अपने स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हुए देश के उज्ज्वल भविष्य के लिए सार्थक क़दम उठाएँ, ताकि वर्ष 2047 में, जब भारत अपनी स्वतंत्रता की शताब्दी मनाएगा, उस समय की पीढ़ी को अपने देश पर गर्व महसूस हो। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि भारत सरकार, राज्य सरकारें और देश के नागरिक भारत के शताब्दी वर्ष को स्वर्ण युग बनाने के उद्देश्य से विकास के पथ पर आगे बढ़ते रहेंगे। राष्ट्रपति का अभिभाषण समाप्त होने के बाद सत्ता पक्ष के साथ-साथ विपक्ष के सदस्यों ने भी उनका अभिवादन किया था।

मुंबई-कामाख्या एसी एक्सप्रेस में दो एसी-3 टियर कोच जोडे जायेंग

अहमदाबाद (ईएमएस) रैलवे ने ट्रेन संख्या 12519/12520 लोकमान्य तिलक टर्मिनस-कामाख्या एसी एक्सप्रेस में दो एसी 3-टियर कोच स्थायी रुप से जोड़ने का निर्णय लिया है। 12519 लोकमान्य तिलक टर्मिनस – कामाख्या एसी एक्सप्रेस में दिनांक 3.4.2022 से और 12520 कामाख्या-लोकमान्य तिलक टर्मिनस एसी एक्सप्रेस में दिनांक 31.03.2022 से जोडे जायेंगे। गाड़ी संख्या 12519/12520 की संशोधित संरचना में एक प्रथम श्रेणी एसी, चार एसी-2 टियर, 14 एसी-3 टियर, एक पेंट्री कार और दो जेनरेटर सह गार्ड की ब्रेक वैन शामिल हैं प्रतीक्षा सूची के यात्रियों से अनुरोध है कि वे ट्रेन में बोर्डिंग से पहले अपने पीएनआर की स्थिति की जांच कर लें। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी और दूसरों की सुरक्षा के लिए कोविड अनुरूप व्यवहार का पालन करें।

गुजरात में फिर बढ़े कोरोना के मामले, 24 घंटे में 26 नए केस, 30 लोग डिस्चार्ज

अहमदाबाद (ईएमएस) गुजरात में फिर एक कोरोना केसों की संख्या में वृद्धि हुई है बुधवार को अहमदाबाद में 8 समेत राज्यभर में कोरोना के कुल 16 मामले थे जो गुरुवार को बढ़कर 26 हो गए जिसमें सबसे अधिक 18 मामले केवल अहमदाबाद में सामने आए हैं गुरुवार को 30 लोगों को ठीक होने के बाद डिस्चार्ज किया गया हैं राज्य में कोरोना से स्वस्थ होने का दर 99.08 प्रतिशत हैं स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक पिछले 24 घंटों में अहमदाबाद कॉर्पोरेशन में कोरोना के 18 केस दर्ज हुए हैं वडोदरा कॉर्पोरेशन में 3, दाहोद, डांग, गांधीनगर कॉर्पोरेशन, वडोदरा और वलसाड में कोरोना का 1-1 समेत राज्यभर में कुल 26 नए मामले सामने आए हैं जबकि 5 कॉर्पोरेशन और 29 जिलों में कोरोना का एक भी केस पिछले 24 घंटों में दर्ज नहीं हुआ वहीं अहमदाबाद, अमरेली, आणंद, अरवल्ली, बनासकांठा, भरुच, भावनगर, बोटाद, छोटाउदेपुर, देवभूमि द्वारका, गांधीनगर, गिर सोमनाथ, जामनगर, जूनागढ़, खेडा, कच्छ, महीसागर, मेहसाणा, मोरबी, नर्मदा, नवसारी, पंचमहल, पाटन, पोरबंदर, राजकोट, साबरकांठा, सूरत, सुरेन्द्रनगर, तापी समेत 29 जिले और भावनगर, जूनागढ़, जामनगर, सूरत और राजकोट समेत 5 कॉर्पोरेशनों में कोरोना का एक भी सक्रिय मरीज नहीं हैं राज्य में फिलहाल 295 एक्टिव केसों में 293 स्टेबल हैं और 2 मरीज वेन्टीलेटर पर हैं अब तक 1212595 लोगों को ठीक होने के बाद डिस्चार्ज किया जा चुका है, जबकि 10942 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी हैं दूसरी ओर राज्य में आज 195444 लोगों का टीकाकरण किया गया जिसमें 18 वर्ष से अधिक आयु के 3321 को पहला और 21105 को कोरोना का दूसरा टीका लगाया गया 15 से 18 वर्षीय आयु के 2887 किशोरों को पहली और 11611 को कोविड की दूसरी वैक्सीन दी गई 12 से 15 वर्षीय 141260 किशोरों को कोरोना का पहला डोज दिया गया जबकि 15260 नागरिकों को प्रीकॉशन डोज दिया गया राज्य में अब तक 105539512 नागरिकों का टीकाकरण हो चुका हैं

आगामी दिनों में शहर समेत राज्यभर में 41.20 लाख से अधिक वाहन जाएंगे स्क्रैप में

अहमदाबाद (ईएमएस) शहर समेत गुजरातभर में आगामी दिनों में 41.20 लाख से भी ज्यादा वाहन स्क्रैप में तब्दील हो जाएंगे स्क्रैप पॉलिसी लागू होते ही सबसे अधिक अहमदाबाद में 20 लाख जितने वाहन कबाड़ बन जाएंगे केन्द्र सरकार ने व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी (वीवीएमपी) को लॉन्च कर दिया हैं इस पॉलिसी के अंतर्गत देश की सड़कों से 15 से 20 साल पुराने वाहन हटाए जाएंगे जिसमें सरकारी और कमर्शियल वाहन 15 पुराने और 20 साल पुराने निजी वाहन स्क्रैप में जाएंगे गुजरात में कुल 70 प्रकार के वाहनों का पंजीकरण किया जाता है और राज्य में कुल 22864144 वाहन पंजीकृत हैं इन वाहनों में 15 वर्ष से या उससे अधिक समय से पंजीकृत वाहनों की संख्या 4120451 हैं 15 वर्ष या उससे अधिक से पंजीकृत वाहनों में 2645959 मोटर साइकिल/स्कूटर, 634049 मोटर कार, 111552 ट्रैक्टर (कृषि), 134153 थ्री व्हीलर (यात्री), 41827 थ्री व्हीलर गुड्स और 175498 गुड्स कैरियर (ट्रक) शामिल हैं अगले एक-दो महीने में स्क्रैप पॉलिसी लागू हो जाएगी और उसके बाद 4120451 वाहन स्क्रैप में चले जाएंगे अगर इन सभी वाहनों को स्क्रैप में भेजा जाएगा तो उसमें सबसे अधिक अहमदाबाद से 2058166 वाहन होंगे राजकोट जिले में 736422 और दक्षिण गुजरात के डांग जिले में सबसे कम 841 वाहन स्क्रैप में जाएंगे पॉलिसी के तहत 15 वर्ष से अधिक पुराने सरकारी और कमर्शियल वाहनों को स्क्रैप किया जाएगा 20 साल से पुराने निजी वाहनों का स्क्रैप किया जाएगा पुराने वाहनों के पुनः पंजीकरण से पहले फिटनेस टेस्ट पास कराना होगा और ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर पर होगा अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों के मुताबिक वाहनों का फिटनेस टेस्ट किया जाएगा एमिशन टेस्ट, ब्रेकिंग सिस्टम, सेफ्टी कम्पोनेंट्स की जांच की जाएगी और फिटनेस टेस्ट में फैल होने पर वाहन को स्क्रैप कर दिया जाएगा गौरतलब है देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन देने और प्रदूषण कम करने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार ने नई पॉलिसी जारी की हैं गुजरात में स्क्रैप वाहनों के लिए प्लांट बनाए जाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं यह प्लांट भावनगर के अलंग में बनेगा केन्द्र सरकार ने देश में 60 से 70 जितने रजिस्टर्ड स्क्रैप बनाने की घोषणा की हैं

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारत को दुनिया में अलग पहचान दिलाई : राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद

- गुजरात विधानसभा में राष्ट्रपति ने कहा-दो गुजराती प्रधामंत्री के साथ काम करने का अवसर मिला

अहमदाबाद (ईएमएस) गुजरात के दो दिवसीय गुजरात दौरे पर गांधीनगर पहुंचे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राज्य विधानसभा को संबोधित करते हुए कहा कि लोकतंत्र के मंदिर में आकर आनंद हुआ हैं उन्होंने कहा कि दो गुजराती प्रधानमंत्री के साथ काम करने अवसर मिला हैं पहले पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई और दूसरे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी हैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारत को दुनिया में अलग पहचान दिलाई हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुजरात विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्षा डॉ. नीमाबेन आचार्य का अभिनंदन किया अपने 19 मिनट के भाषण में राष्ट्रपति ने कहा कि यह एक महत्वपूर्ण संयोग है कि जब आजादी के अमृत महोत्सव के विधानसभा की कार्यवाही चल रही हैं 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में दादाभाई नवरोजी और फिरोजशा जैसे लोगों ने आजादी की आवाज बुलंद की गांधी जी ने न केवल स्वतंत्रता दिलाई बल्कि दुनिया को एक नया रास्ता भी दिखाया आज दुनिया में जहां भी हिंसा होती है तब गांधी जी को याद किया जाता हैं राष्ट्रपति ने कहा कि नमक सत्याग्रह और दांडी कूच ने स्वतंत्रता संग्राम को एक स्वरूप दिया था स्वतंत्रता संग्राम ने ही सरदार पटेल जैसे नेता देश को भेंट किया था उन्होंने केवडिया में सरदार पटेल की सबसे विराट प्रतिमा का उल्लेख करते हुए कहा कि लोगों के दिल में सरदार का स्थान उससे भी विराट था संत नरसिंह मेहता का भजन 'वैष्णव जन' स्वतंत्रता संग्राम के लिए खास गीत बन गया था राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि सोमनाथ पर आक्रमण से लेकर 2001 के भूकंप जैसी अनेक त्रासदियां झेलने के बावजूद गुजरात मजबूती के साथ उठ खड़ा हुआ हैं गुजरात ने देश को विक्रम साराभाई जैसा महान वैज्ञानिक दिया हैं गुजरात के लगातार आर्थिक विकास के लिए राष्ट्रपति ने पूर्व मंत्री और सरकारों का भी अभिनंदन किया और कहा कि श्वेत क्रांति से यह परिवर्तन संभव हुआ हैं राज्य में सहकारिता क्षेत्र अग्रसर हैं केन्द्र में सहकार विभाग बनाया है और उसकी कमान गुजरात के अमित शाह के हाथ में हैं उन्होंने गुजरात के सर्वांगीण विकास के लिए महत्वपूर्ण कानून बनाने के लिए गुजरात विधानसभा का अभिनंदन किया डॉ. नीमाबेन आचार्य के रूप में गुजरात विधानसभा को पहली महिला अध्यक्षा मिली हैं अहमदाबाद स्थित साबरमती आश्रम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विख्यात होने का उल्लेख करते हुए राष्ट्रपति ने रिवरफ्रंट को शहरीकरण का आदर्श उदाहरण बताया राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि गुजरातियों का देशप्रेम जगजाहिर हैं

२५ से २८ चार दिन राज्य में हीटवेव, यलो अलर्ट घोषित

अहमदाबाद, २४ मार्च ।

मार्च की शुरूआत में रिकॉर्ड तोड़ने के बाद गर्मी कम होने पर लोग राहत अनुभव कर रहे है । लेकिन अब शुक्रवार से चार दिन के लिए यलो अलर्ट के साथ हीटवेव रहने का पूर्वानुमान लगाया गया है । फिर एक बार गर्मी का तापमान बढ़ने पर गर्मी का तापमान ४० को पार कर जाने की प्रबल संभावना है । इसके साथ लू लगने से बचने के लिए उपाय करने के लिए मौसम विभाग द्वारा बताया गया है । आज राज्य में न्यूनतम तापमान २६ डिग्री और अधिकतम तापमान ३९ डिग्री दर्ज किया गया है । अहमदाबाद सहित राज्य के सौराष्ट्र, उत्तर गुजरात और कच्छ में हीटवेव रहने का पूर्वानुमान लगाया गया है । तारीख २५ से २८ मार्च के दौरान यलो अलर्ट दिया गया है इसके दौरान दोपहर के समय में भीषण गर्मी का अनुभव होगा और हीटवेव रहेगा । कल राज्य के सौराष्ट्र के गीर सोमनाथ और कच्छ हीटवेव का असर होगा । जिसके बाद शनिवार को बनासकांठा, साबरकांठा, मेहसाणा, पाटण सहित सौराष्ट्र के भावनगर, पोरबंदर, जूनागढ़, गीर सोमनाथ, राजकोट और कच्छ तथा दीव में हीटवेव का अनुभव किया जाएगा । चौथे दिन यानी कि २७ मार्च को अहमदाबाद और गांधीनगर सहित राज्य के बनासकांठा, साबरकांठा, मेहसाणा, पाटण में हीटवेव की वजह से गर्मी का तापमान बढ़ जाएगा ।

इस दिन में सौराष्ट्र के अमरेली, सुरेन्द्रनगर, बोटाद, भावनगर, पोरबंदर, जूनागढ़, गीर सोमनाथ, राजकोट और कच्छ में तथा दीव में हीटवेव की वजह से गर्मी का तापमान बढ़ जाएगा ।

फिनो पेमेंट्स बैंक राजस्थान रॉयल्स का डिजिटल पेमेंट्स पार्टनर बना

इस गठबंधन का उद्देश्य भारत में फिनो की सेवाओं का उपयोग बढ़ाना है

मुंबई, -- मार्च, 2022: फिनो पेमेंट्स बैंक ("फिनो बैंक", "फिनो") ने घोषणा की है कि यह भारत की सबसे बड़ी प्रीमियर क्रिकेट प्रतियोगिता के सीज़न 15 में राजस्थान रॉयल्स का ऑफिशियल *डिजिटल पेमेंट्स पार्टनर* होगा।

फिनो पेमेंट्स बैंक के सीएमओ, आनंद भाटिया ने कहा, "प्रतिस्पर्धात्मकता और निष्ठा ब्रांड के वो गुण हैं, जो फिनो पेमेंट्स बैंक को राजस्थान रॉयल्स से मजबूती से जोड़ते हैं। दोनों के इन समान गुणों ने इस गठबंधन में मुख्य भूमिका निभाई है।"

प्रतियोगिता की सबसे मनोरंजक टीम के रूप में मशहूर और 2008 में पहली क्रिकेट प्रतियोगिता के विजेता रहे, राजस्थान रॉयल्स (आरआर) के साथ इस गठबंधन द्वारा फिनो ने पहली बार इस मेगा स्पोर्टिंग ईवेंट में प्रवेश किया है।

भारत के डिजिटल बैंक के रूप में, फिनो बैंक को राजस्थान रॉयल्स, लीग एवं क्रिकेट के खेल से जुड़े व डिजिटल योग्यता रखने वाले उपभोक्ताओं के बीच अपनी विज़िबिलिटी बढ़ाने का अवसर मिलेगा।

इस गठबंधन के बारे में, ऋषि गुप्ता, एमडी एवं सीईओ, फिनो पेमेंट्स बैंक ने कहा, "भारत में क्रिकेट और सिनेमा मनोरंजन के सबसे बड़े साधन हैं, जिन्हें पूरे भारत के लोग पसंद करते हैं। हम राजस्थान रॉयल्स और क्रिकेट के खेल के साथ जुड़कर गर्व व खुशी महसूस कर रहे हैं। राजस्थान रॉयल्स नॉन–मेट्रो एवं छोटे शहरों से क्रिकेटिंग की प्रतिभा को बढ़ावा देने के लिए मशहूर है, जो हमारे मुख्य बाजार हैं। हमारे लिए शहरी एवं ग्रामीण इलाकों के मिलेनियल उपभोक्ताओं तक पहुंचने का यह एक बेहतरीन अवसर है, जिसके माध्यम से हम उन्हें फिनो की डिजिटल पेमेंट सेवाओं को तलाशने का साधन प्रदान कर सकते हैं।"

पश्चिम रेलवे संशोधित ट्रेन नंबरों के साथ नियमित ट्रेनों के रूप में पांच त्यौहार स्पेरशल ट्रेनें चलाएगी

अहमदाबाद ,यात्रियों की सुविधा तथा उनकी मांग को पूरा करने के लिए पांच त्योंहार स्पेसशल ट्रेनों को नियमित किया जा रहा है। अतएव, ये ट्रेनें अब जुलाई, 2022 से संशोधित नियमित ट्रेन नंबरों के साथ चलेंगी। पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी सुमित ठाकुर द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार इन ट्रेनों का विवरण इस प्रकार हैः-

1. ट्रेन नंबर 02989 दादर-अजमेर सुपरफास्टा स्पेशल जिसे 30 जून, 2022 तक अधिसूचित किया गया था, उसे 2 जुलाई, 2022 से ट्रेन नंबर 12989 दादर-अजमेर एक्सप्रेस के रूप में नियमित किया जा रहा है।

2. ट्रेन संख्या 09707 बांद्रा टर्मिनस-श्रीगंगानगर स्पेशल जिसे 02 जुलाई, 2022 तक अधिसूचित किया गया था, उसे 3 जुलाई, 2022 से ट्रेन नंबर 14702 बांद्रा टर्मिनस-श्री गंगानगर अमरापुरा अरावली एक्सप्रेस के रूप में नियमित किया जा रहा है।

3. ट्रेन संख्या 02474 बांद्रा टर्मिनस-बीकानेर सुपरफास्ट स्पेशल जिसे 28 जून, 2022 तक अधिसूचित किया गया था, उसे 5 जुलाई, 2022 से ट्रेन नंबर 22474 बांद्रा टर्मिनस-बीकानेर एक्सप्रेस के रूप में नियमित किया जा रहा है।

4. ट्रेन नंबर 02490 दादर-बीकानेर सुपरफास्टन स्पेशल जिसे 29 जून, 2022 तक अधिसूचित किया गया था, उसे 3 जुलाई, 2022 से ट्रेन नंबर 12490 दादर-बीकानेर एक्सप्रेस के रूप में नियमित किया जा रहा है।

5. ट्रेन नंबर 04818 दादर-भगत की कोठी सुपरफास्टन स्पेशल जिसे 1 जुलाई, 2022 तक अधिसूचित किया गया था, उसे 5 जुलाई, 2022 से ट्रेन नंबर 20484 दादर-भगत की कोठी एक्सप्रेस के रूप में नियमित किया जा रहा है।

ट्रेन संख्या 12989, 14702, 22474, 12490 एवं 20484 की बुकिंग 25 मार्च, 2022 से यात्री आरक्षण केन्द्रों और आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर शुरू होगी।

ट्रेनों के परिचालन समय, ठहराव और संरचना से सम्बंधित विस्तृत जानकारी के लिए यात्री .हल्ग्ब.र्ग्हैं ग्तु.दन.ग्ह पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

मीडिया ट्रायल में रहनेवाले लोग पहले 28 साल तक शासन करें उसके बाद बात करें

- गुजरात के शिक्षा मंत्री जीतु वाघाणी का दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर पलटवार

अहमदाबाद (ईएमएस) गुजरात के शिक्षा मंत्री जीतु वाघाणी ने कहा कि शिक्षा के माध्यम द्वारा मीडिया ट्रायल में रहनेवाले लोग पहले 28 वर्ष तक शासन करें और उसके बाद शिक्षा की बात करें लोकतंत्र में चुनाव के लिए कई मैदान हैं परंतु हमारे मन तो जनता जनार्दन की सेवा ही मैदान हैं जनता जनार्दन ही हमारे मन में भगवान हैं इसीलिए जनता का अविरत आशीर्वाद लगातार 28 साल से हमें प्राप्त हो रहा हैं बता दें कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री एवं शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने गुजरात की शिक्षा नीति पर सवाल उठाते हुए खुली बहस करने की गुजरात के शिक्षा मंत्री जीतु वाघाणी को ट्वीटर के जरिए चुनौती दी थी गुजरात सरकार के प्रवक्ता मंत्री जीतु वाघाणी ने आम आदमी पार्टी द्वारा शिक्षा के बारे में डिबेट करने की दी गई चुनौती खारिज करते हुए कहा कि तुलना किसी के साथ नहीं हो सकती विकास के सूचकांक में प्लानिंग कमीशन, नीति आयोग के आधार पर ही कोई रैकिंग मिलता हैं गुजरात सभी सेवा क्षेत्रों में देशभर में आज भी अग्रसर है, जिसे देख ऐसे लोगों के पेट में मरोड उठती हैं इसीलिए ऐसे आधारहीन आरोप लगाकर गुजरात को बदनाम करने निकले हैं, जिसे राज्य सरकार कभी बर्दाश्त नहीं करेगी राज्य के प्रवक्ता मंत्री एवं शिक्षा मंत्री जीतु वाघाणी ने कहा कि अन्य कोई भी राज्य की गुजरात के साथ तुलना नहीं की जा सकती कई लोग सत्ता के मद में और नशे में आकर 'हम पंजाब जीते, दिल्ली में दो बार जीते' जैसी बातें करते हैं इन दोनों राज्यों और उसकी जनता के प्रति सम्मान है, परंतु गुजरात की जनता ने भाजपा की सरकार को लगातार 28 साल तक शासन करने का अधिकार दिया हैं केशूभाई पटेल के नेतृत्व से लेकर विजय रूपाणी तक और अब भूपेन्द्र पटेल के नेतृत्व में राज्य की जनता ने भाजपा को मेन्डेट दिया हैं इसलिए किसी से तुलना कोई प्रश्न ही नहीं उठती यह तुलना तभी संभव है जब कोई लगातार 28 वर्ष तक शासन में रह सके जीतु वाघाणी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि गुजरात कोई ऐसा मैदान नहीं है, जहां कोई भी हीरोगिरी कर सके केवल मीडिया में बने रहने के लिए मीडिया ट्रायल का हिस्सा बनने के लिए लगातार कुछ लोग ऐसी बातें करते रहते हैं लेकिन यह गुजरात की धरती है और इस धरती ने समयांतर ऐसे लोगों को सबक सिखाया हैं जनता जनार्दन ही सबसे बड़ी शक्ती हैं उन्होंने मीडिया ट्रायल करनेवालों की आलोचना करते हुए कहा कि गुजरात की जनता 2014 और 2019 में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सभी 26 सीटें भाजपा को दी थी अगर आम आदमी पार्टी का शासन इतना ही अच्छा है तो वर्ष 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में उसका हाल क्या हुआ था? इसका जवाब उनसे मांगा जाना चाहिए शिक्षा मंत्री ने कहा कि लोकतंत्र है इसलिए कोई भी आ सकता है, परंतु पुराना इतिहास खंगाल लेना कि पहले हुए विधानसभा, लोकसभा, कॉर्पोरेशन, जिला और तहसील पंचायतों के चुनावों में जनता ने भाजपा को स्वीकार किया हैं हमारे लिए पहले भगवान सोमनाथ और दूसरे भगवान जनता जनार्दन हैं उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने जो किया है वह जनता जानती है और इसीलिए लोकसभा की सभी सीटें उसे दी हैं हमने इस जिम्मेदारी को स्वीकार किया हैं लगातार 6 बार हमे गुजरात की जनता ने स्वीकार किया हैं राज्य में सरकारी 33 हजार प्राथमिक और 7 हजार माध्यमिक समेत 40000 स्कूलें हैं दिल्ली में 1054 स्कूलों में से केवल 54 स्कूलें स्मार्ट स्कूल हैं, जबकि गुजरात में 10 हजार स्कूलें स्मार्ट स्कूल हैं उन्होंने कहा कि वर्ष 2030 तक 154 स्कूलों को स्मार्ट बनाने का कुछ लोगों ने दावा किया हैं जबकि हमारा आगामी दिनों में 15 हजार प्राथमिक स्कूलों समेत कुल 20 हजार स्कूलों को स्मार्ट स्कूल बनाने का आयोजन हैं गुजरात में 70 लाख विद्यार्थी हैं, जबकि कुछ राज्यों में 15 लाख विद्यार्थी हैं नतीजतन यह तुलना संभव है ही नहीं किसी के साथ तुलना कर नहीं बल्कि सेवा कर जनता के हृदय में बसा जा सकता हैं

हाईकोर्ट का हेल्मेट का नियम सख्ती से लागू करने का आदेश

अहमदाबाद (ईएमएस) गुजरात हाईकोर्ट ने कन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट की एक पिटिशन की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को हेल्मेट के कानून का सख्ती से अमल करने का आदेश दिया हैं हाईकोर्ट के मुख्य न्यायधीश ने कहा कि लोगों की सुरक्षा काफी जरूरी है और इसके लिए कानून लागू करने में कोई ढील नहीं होनी चाहिए हम रात या दिन के दौरान बाहर निकलते हैं तो कई टू व्हीलर चालक बगैर हेल्मेट वाहन चलाते दिखाई देते हैं, इसकी वजह क्या है? हेल्मेट के कानून का कड़ाई से पालन नहीं कराया जा रहा है या हेल्मेट पहनना अनिवार्य नहीं क्या है? हाईकोर्ट की सख्ती के बाद मुख्य सरकारी वकील ने अदालत को आश्वस्त किया है कि राज्य में हेल्मेट के कानून का कड़ाई से अमल कराया जाएगा हेल्मेट नहीं पहनने वाले टू व्हीलर चालकों के कानूनी कार्यवाही किए जाने का सरकारी वकील ने आश्वासन दिया हैं मुख्य न्यायधीश ने सरकारी वकील का इस ओर भी ध्यान आकृष्ट किया कि हेल्मेट कानून का सख्ती से अमल कराने के दौरान पुलिस और वाहन चालकों के बीच जुबानी जंग और घर्षण भी हो सकता है, जिसके लिए पुलिस और ट्रैफिक पुलिस को तैयार रहना होगा

दिल्ली के शिक्षा मंत्री की गुजरात के शिक्षा मंत्री को शिक्षा चर्चा की खुली चुनौती

अहमदाबाद (ईएमएस) इस वर्ष के अंत में गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत गरमाने लगी हैं गुजरात भाजपा की ओर से दिल्ली की स्कूलों के खिलाफ किए जा रहे ट्वीट को लेकर दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने गुजरात के शिक्षा मंत्री जीतु वाघाणी की शिक्षा पर खुली बहस की चुनौती दी हैं मनीष सिसोदिया ने इस संदर्भ में ट्वीट किया है, जिसमें लिखा – "कल से बीजेपी गुजरात दिल्ली के स्कूलों के खिलाफ ट्वीट कर रही हैं गुजरात में 'आप' के बढ़ते प्रभाव और पंजाब चुनाव नतीजों से आपको बौखलाहट हो रही हैं भाजपा शिक्षा की बात ना ही करे तो अच्छा हैं मैं गुजरात के शिक्षा मंत्री जीतु वाघाणी को डिबेट के लिए चैलेंज करता हूँ शिक्षा का गुजरात मोडल अच्छा या दिल्ली का इस पर्चा करेंगे स्थान व समय आपका" बता दें कि गुजरात भाजपा ने दिल्ली की शिक्षा नीति पर कई सवाल उठाते हुए ट्वीट किए थे गुजरात भाजपा ट्वीट कर सवाल किया "आप सरकार ने 20000 गेस्ट टीचर्स को बर्खास्त क्यों किया?" अन्य एक ट्वीट में कहा " केजरीवाल की एज्युकेशन सिस्टम फैल हो चुकी हैं केजरीवाल सरकार वॉकेशनल ट्रेनर्स का शोषण कर रहे हैं केजरीवाल के नेतृत्व में शिक्षक धरना दे रहे हैं" गुजरात ही नहीं दिल्ली भाजपा ने भी ट्वीट कर दिल्ली में शिक्षा नीति को लेकर सवाल उठाए हैं दिल्ली भाजपा ने ट्वीट कर कहा "आप की सरकार ने लोगों के साथ विश्वासघात किया हैं न तो बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया, ना ही गेस्ट टीचर्स को वेतन दिया और ना ही आंगनवाडी कर्मचारियों को मानद वेतन बढ़ाया मतलब प्रचार के अलावा आप और कुछ नहीं कर पाई हर साल आप और शिक्षा मंत्री के पास गेस्ट